भारत और शंघाई सहयोग संगठन

तीन निबंध

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली
2020

भारत और शंघाई सहयोग संगठन

तीन निबंध

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

2020

I. विषय-वस्तु

प्रस्तावना.....**7**

भारत और शंघाई सहयोग संगठन

योगेंद्र कुमार.....**9**

भारत के संदर्भ में शंघाई सहयोग संगठन के उद्देश्य एवं प्रासंगिकता - आकलन

पी. स्टोबदान.....**35**

एससीओ, अफगानिस्तान एवं क्षेत्रीय सुरक्षा

पी. स्टोबदान.....**61**

प्रस्तावना

भारत साल 2017 में शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। यह जल्द ही एससीओ के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने वाला है। इस महत्वपूर्ण अंतरसरकारी संगठन से संबंधित मौजूदा ज्ञान और सूचित चर्चा के बढ़ाने हेतु परिषद ने ताजिकिस्तान के पूर्व राजदूत श्री योगेंद्र कुमार और किर्गिस्तान के पूर्व राजदूत प्रो. पी. स्टोबदान से इस संगठन के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव के संदर्भ में एससीओ के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का अनुरोध किया। दोनों लेखक एससीओ क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनके निबंध क्षेत्रीय सहकारी तंत्रों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों की बारीकियों, जटिलताओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। प्रो. स्टोबदान ने इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से उभर रहे क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी संक्षिप्त जानकारी दी है।

आईसीडब्ल्यूए को उम्मीद है कि ये तीनों शोध-पत्र भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एचओजी शिखर सम्मेलन के आयोजन तक एससीओ से संबंधित ज्ञान को बढ़ाएंगे और बहस को व्यापक बनाने का काम करेंगे।

इन तीनों निबंधों में दिए गए विचार, विश्लेषण और सिफारिशें लेखकों के व्यक्तिगत हैं।

टी. सी. ए. राघवन
महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए)

सप्रू हाउस
25 नवंबर, 2020

भारत और

शंघाई सहयोग संगठन

योगेंद्र कुमार

कार्यकारी सारांश

- 2001 में स्थापित एससीओ, चीनी पहल पर विकसित किया गया है, जिसकी उत्पत्ति का कारण रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ देश की सीमाओं का समझौता है। संवेदनशील झिंजियांग क्षेत्र के नजदीक चीन की परिधि के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, इसे 'अमेरिका के नेतृत्व वाले एकध्रुवीय विश्व के खिलाफ' एक 'बहुध्रुवीय वैश्विक क्रम' के निर्माण खंड के रूप में, रूस और तीन मध्य एशियाई देशों - और बाद में उज्बेकिस्तान के साथ - 'गैर-पश्चिम' 'संगठन विकसित करने के साझा हित प्राप्त हुए ।

- "संप्रभुता के पारस्परिक सम्मान", स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता और राज्य की सीमाओं की अनुल्लंघनीयता, अनाक्रमण/अहस्तक्षेप, ताकत/धमकी के बल का इस्तेमाल न करना, "निकटवर्ती क्षेत्रों में कोई एकतरफा सैन्य श्रेष्ठता नहीं", और विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की "शंघाई भावना" को मूर्त रूप देने के लिए संगठन राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति में, और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों में सदस्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है ।

- एक बहुस्तरीय प्रणाली के रूप में, इसमें राज्य परिषद के प्रमुख, सरकारी परिषद के प्रमुख, और संसद, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, आपदा प्रतिक्रिया वगैरह के साथ-साथ व्यापार और विशिष्ट संवादात्मक उद्देश्यों के लिए गैर-सरकारी मंचों जैसे अन्य राज्य अंगों के प्रमुख होते हैं। इसका बीजिंग में स्थित एक सचिवालय है और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी

संरचना की कार्यकारी समिति है जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की "तीन बुराइयों" का मुकाबला करती है।

- 2017 में, भारत और पाकिस्तान सदस्यों के रूप में शामिल हुए; उनके साथ ने सार्क के साथ चीन को जानबूझकर आईना दिखाया है। इसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को प्रेक्षक देशों के रूप में रखा गया है और अज़रबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, श्रीलंका, तुर्की और नेपाल संवाद भागीदारों के रूप में। इसने संयुक्त राष्ट्र, उसके संबद्ध निकायों और यूरेशिया और अफ्रीका में अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। 2005 में पर्यवेक्षक की स्थिति के लिए अमेरिकी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। मध्य एशियाई देशों ने अपनी 'प्रतिरक्षा' रणनीतियों का पालन करते हुए रूस और चीन के अलावा अन्य देशों और शीत युद्ध के बाद के कई क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंध विकसित किए हैं। सबसे हालिया सी5+1 (पाँच मध्य एशियाई देशों और अतिरिक्त-क्षेत्रीय देश) संवाद प्रक्रिया है, जिसमें न केवल चीन बल्कि भारत सहित कई अन्य देश शामिल हैं।

- इसके विकास को प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रमों जैसे कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण (2001), यूरेशियन क्षेत्र में मिसाइल रक्षा बैटरियों की अमेरिकी तैनाती (2007) और ट्रम्प प्रशासन की अफगानिस्तान के लिए नई रणनीति (2017) द्वारा आकार दिया गया है; बहुपक्षीय एजेंसी इंटरैक्शन के लिए एक व्यापक नेटवर्क के बावजूद, इसकी कमजोर संस्थागत डिजाइन, बड़ी शक्तियों के लिए अपने द्विपक्षीय रिश्तों के माध्यम से रणनीतिक परिवेश को आकार देने के लिए पर्याप्त स्थान की अनुमति देती है।

क्षेत्र के लिए 'सुरक्षा' और 'अर्थव्यवस्था' के बीच रूस-चीन का एक अनौपचारिक कार्य विभाजन, अफगानिस्तान में गहराते हुए सामरिक तरलता के कारण भयावह है। मध्य एशिया में, कोविड-19 महामारी, मंद अर्थव्यवस्था, उच्च ऋणग्रस्तता और शिनजियांग स्थिति के कारण बढ़ती चीनी विरोधी भावना के कारण नई चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं।

- भारत के मध्य एशिया के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। मध्य एशिया और दक्षिण-पश्चिम एशिया के बीच शक्ति संतुलन की प्रकृति के साथ परस्पर संवादात्मक प्रकृति के रणनीतिक विकास में भी इसकी रुचि है। रूस इसे क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक संतुलानकर्ता के रूप में देखता है और चीन, दक्षिण एशिया में इसके खिलाफ 'संतुलनकारी' चाल चलता है। भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति का उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। एससीओ सदस्य के रूप में, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, खनिज, क्षमता निर्माण, विकास साझेदारी और व्यापार और निवेश में सहयोग पर ध्यान केंद्रित है। बीआरआई की परोक्ष आलोचना में, भारत का जोर संप्रभुता, समावेशिता और स्थिरता पर आधारित कनेक्टिविटी पर है। यह अफगानिस्तान में एससीओ की संभावित भूमिका का समर्थन करता है। महामारी के दौरान, स्वास्थ्य सेवा, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ इसके सहयोग का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है।

- पेपर की प्रमुख सिफारिशें, महामारी और एलएसी और एलओसी पर तनाव के कारण परिवर्तित क्षेत्रीय भू-राजनीति के संदर्भ में, एससीओ के चार्टर सिद्धांतों सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के स्वीकृत मानदंडों पर जोर देने के माध्यम से भारतीय कूटनीति को आधार बनाना है, और इस क्षेत्र के लिए और उससे आगे एक अधिक न्यायसंगत, स्थायी कोविड के बाद के भविष्य

को बढ़ावा देना है। यह चीनी आक्रामकता और उसके ऋण जाल कूटनीति दोनों से संबंधित है। यह रूस सहित एक जैसी सोच वाले देशों के सहयोग से और जमीनी स्तर के समुदायों को शामिल करते हुए सतत विकास पर त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है। बेहतर धारणा प्रबंधन के लिए एक प्रभावी मीडिया आउटरीच नीति की आवश्यकता है। एससीओ के आतंकवाद-विरोधी ढांचे और एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह के साथ प्रभावी जुड़ाव के लिए पर्याप्त कर्मियों का समर्थन होना महत्वपूर्ण है।

शंघाई सहयोग संगठन का उद्भव और संस्थागत विकास

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की उत्पत्ति और संस्थागत विकास शीत युद्ध के अंत के बाद से यूरेशियन हार्टलैंड भू-राजनीति के घुमावों और मोड़ों में मानकों के रूप में काम कर सकता है। सोवियत संघ के विघटन (1991) के साथ, भारत के रणनीतिक दाँवों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अब महामारी की अंधेरी छाया के साथ, यूरेशियन हृदय क्षेत्र में शक्ति के संतुलन, मध्य एशियाई क्षेत्रीय भूराजनीति पर इसके प्रभाव, और मध्य एशिया और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक विकास में लगातार बदलते संबंधों का भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा पहले से कहीं अधिक बारीकी से अवलोकन किया जा रहा है। 1991 तक, भारत-सोवियत संबंधों की व्यापक प्रकृति ने इस क्षेत्र के प्रति भारतीय परिप्रेक्ष्य को अनुकूलित किया।

एक 'गैर-पश्चिम' पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पत्ति

सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के 'पेरेस्त्रोइका', सोवियत संघ और चीन के बीच सीमा वार्ता की एक प्रक्रिया, जिस पर दोनों देशों ने उससुरी नदी पर पूर्व में और पश्चिम में शिनजियांग सीमा पर एक तीव्र लघु संघर्ष (1969) किया था, के कारण बदली हुई अनुकूल परिस्थितियों के साथ लॉन्च किया गया था जो रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभरने के बाद जारी रहा। सीमा का निपटान भी झिंजियांग से सटे उनकी संबंधित सीमाओं पर विश्वास निर्माण के लिए संधि व्यवस्था के साथ हुआ और 1996 में शंघाई पाँच समूह का जन्म हुआ। उज़बेकिस्तान के प्रवेश (2001) के साथ, समूह का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया, जिसने 2002 में अपना घोषणापत्र अपनाया। पहले से ही नींव प्रदान करने वाले तैयारी के काम के साथ, यह 'विकासवादी' विभक्ति बिंदु अमेरिका के एकपक्षीय मानवाधिकार एजेंडे की

प्रतिक्रिया थी। अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के हस्तक्षेप (7 अक्टूबर 2001) को मध्य एशियाई देशों का समर्थन प्राप्त था; बेस / स्टेजिंग पोस्ट (किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़बेकिस्तान) सहित गठबंधन की विस्तारित सैन्य उपस्थिति, जबकि रूस (और चीन) के खिलाफ बाहरी संतुलन के लिए उत्तोलन के रूप में प्रयोग की गई थी, वह शासन स्थिरता पर समन्वित रूप से चिंताओं को और गहरा बनाता था, जैसा कि, 2005 में अंदिजान (उज़बेकिस्तान) नरसंहार और किर्गिस्तान में "ट्यूलिप रेवोल्यूशन" के उदाहरण से स्पष्ट है । 2005 के एससीओ घोषणा ने अमेरिका से, एससीओ के सदस्य राज्यों से अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए एक स्पष्ट समय सारिणी माँगी और, बाद में उसी वर्ष, उज़बेकिस्तान ने उसका बेस वहाँ बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब रूसी और चीनी समकक्ष अफगानिस्तान में सैन्य अभियानों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो बुनियादी ढांचे में पारगमन / किराए के लिए यूएस और पश्चिमी भुगतान और अन्य प्रकार की पश्चिमी सहायता, पाइपलाइनों और रेलवे परियोजनाओं में तेजी से चीनी निवेशों और मजबूत आर्थिक संबंध से ओवरशैडो की जाने लगी ।

बड़ा रणनीतिक उद्देश्य, एससीओ को 'एकध्रुवीय', जो सोवियत संघ के गायब होने के साथ अस्तित्व में आया था, के बजाए एक 'बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था' बनाने के प्रयास में गैर-पश्चिम' पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में विकसित करना था।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार और विकास

एक ही भू-राजनीतिक उद्देश्य उस समय के आसपास अपनी अंतरराष्ट्रीय भूमिका के विस्तार को रेखांकित करता है। 2005 में, भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान ने पर्यवेक्षकों (अधोमुख राज्य के प्रमुखों से सभी स्तरों पर अप्रतिबंधित बैठकों में गैर-मतदान भागीदारी) के रूप में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया; वर्तमान पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान (2012), बेलारूस (2015), ईरान (2005), और मंगोलिया (2005) हैं। संवाद भागीदार की एक श्रेणी (प्रासंगिक मंत्रिस्तरीय बैठकों में भागीदारी और एससीओ+ संवाद भागीदार मीटिंग, वर्किंग ग्रुप, गैर-वर्गीकृत दस्तावेजों की प्राप्ति, सहयोग समझौतों और निर्णय लेने में गैर-भागीदारी) 2008 में बनाई गई थी; वर्तमान संवाद भागीदार अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया (2008 में तीनों), श्रीलंका (2009), तुर्की (2012) और नेपाल (2015) हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ सदस्य बने; संगठन में शामिल होने वाला पाकिस्तान चीन के आग्रह पर था जो भारत की उपस्थिति को संतुलित करना चाहता था, जबकि रूस, मध्य एशिया में बढ़ते चीनी पदचिह्न के बारे में असहज [1]था और उसी उद्देश्य के साथ भारतीय सदस्यता के लिए उत्सुक था। एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान), कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस), तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र (2004), सीआईएस (2005), आसियान (2005), सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएस टीओ, 2007)[2], आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ, 2007)[3], ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (2011), एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन(सीआईसीए, 2014)[4], एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग और प्रशांत (2015), और अफ्रीकी संघ (2018) के साथ सम्बन्ध स्थापित किए ।

पर्यवेक्षक की स्थिति में दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों में बांग्लादेश, पूर्वी तिमोर, मिस्र, सीरिया, इजरायल, मालदीव, यूक्रेन, इराक और सऊदी अरब में बहरीन और कतर ने सदस्य होने की इच्छा जाहिर करने की सूचना दी है।[5] चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के उठाने के बाद जनवरी 2016 में ईरान की सदस्यता के लिए समर्थन की घोषणा की थी। विभिन्न श्रेणियों के तहत भाग लेने वाले विभिन्न देशों की रुचि समय में एक विशिष्ट बिंदु पर उनकी अपनी बदलती विदेश नीति के दृष्टिकोण को दर्शाती है। 2005 में ऑब्जर्वर के दर्जे के लिए अमेरिकी आवेदन को खारिज कर दिया गया था।[6]

संस्थागत संरचना

इसके घोषित लक्ष्य[7] हैं "सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसी-धर्म को मजबूत करना; राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना; क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना; और एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक आदेश की स्थापना की ओर बढ़ना।" यह संगठन के संस्थापक सिद्धांतों को संदर्भित करने के लिए भी प्रासंगिक है जैसा कि इसके चार्टर के अनुच्छेद 2 में वर्णित है, जिसमें "संप्रभुता, स्वतंत्रता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति "पारस्परिक सम्मान" और राज्य की सीमाओं की अनुलंघनीयता, गैर-आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप, बल का गैर-उपयोग या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके उपयोग की धमकी न देना, आसन्न क्षेत्रों में एकतरफा सैन्य श्रेष्ठता की माँग न करना", सदस्य राज्यों के बीच समानता, और "सदस्य राज्यों के विवादों का शांतिपूर्ण समाधान" शामिल है

उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय राज्य परिषद के प्रमुख होते हैं जो वर्ष में एक बार मिलते हैं । सरकारी प्रमुखों की परिषद भी, वर्ष में एक बार बैठक करती है, सहयोग रणनीति, आर्थिक और अन्य सहयोग मुद्दों पर चर्चा करती है, और वार्षिक बजट को मंजूरी देती है। इसके अलावा, संसद के प्रमुखों की; राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की; विदेशी मामलों, रक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, अर्थव्यवस्था, परिवहन, संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के मंत्रियों की; कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों, सर्वोच्च और मध्यस्थता अदालतों; और महा अभियोजकों की बैठकें होती हैं। एक राष्ट्रीय समन्वयक परिषद भी है। जैसा कि अनुबंध-ए (पृष्ठ 32) से स्पष्ट होगा, कई मंत्री कार्य समूह और संस्थाएं हैं जैसे व्यापार परिषद, इंटरबैंक कंसोर्टियम और साथ ही एससीओ फोरम (ट्रैक II)।

इसके दो स्थायी निकाय हैं। एक बीजिंग में स्थित सचिवालय, जिसका नेतृत्व एक गैर-विस्तार योग्य तीन साल के कार्यकाल के लिए एक महासचिव द्वारा किया जाता है; यह संगठन की गतिविधि का समन्वय करता है, पर्यवेक्षक राज्यों और संवाद भागीदारों के साथ सहयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय संचालनों के साथ सहयोग करता है और गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करता है। दूसरी, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (आरएटीएस)[8] की ताशकंद आधारित कार्यकारी समिति है; उत्तरवर्ती 2004 में अस्तित्व में आया, जो अफगानिस्तान में तालिबान के पुनरुत्थान के साथ-साथ सदस्य देशों के अन्य इस्लामी कट्टरपंथी और अतार्किक तत्वों के साथ हुआ था। आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद की "तीन बुराइयों" को मिलाकर, यह "कार्य संपर्क" को बनाए रखता है, जिसमें सदस्य राज्यों के साथ उनके निवासी स्थायी प्रतिनिधियों के माध्यम से डेटाबैंक का रखरखाव शामिल है, और इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसकी आतंकवाद-रोधी समिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों की तैयारी में भाग लेना शामिल है।[9] आरएटीएस ने भी अभ्यास

किया है, जैसे कि एक काउंटर-न्यूक्लियर आतंकी अभ्यास, और आतंकवादी समूहों को पकड़ने या समाप्त करने का दावा किया ।[10] उदाहरण के लिए, 2011 से 2015 के बीच, एससीओ के सदस्य राष्ट्रों ने 20 नियोजित आतंकवादी हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल की, 440 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को निष्प्रभावी किया, 213 आतंकवादियों / अतिवादियों और मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने के अलावा 213 आतंकवादियों / चरमपंथियों और आतंकवादी संगठनों के 1700 सदस्यों का प्रत्यर्पण किया।[11]

यूरेशियन भू-संरचनात्मक प्रसार में एससीओ (और 'इंडो-पेसिफिक')

केन्द्रीय एशियाई देशों का बाह्य अभियान

शीत युद्ध के अंत ने यूरेशियन भू-संरचनात्मक प्रसार में बड़े शक्ति तनाव को कम कर दिया लेकिन एक अलग गतिशीलता का संचार किया । इसकी सुरक्षा वास्तुकला ने इस स्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों को रास्ता दिया जो नए लोगों को, जो तेजी से बदलती परिस्थितियों के साथ तेजी से उभर रहे हैं, को प्रभावित करने के लिए जूझ रहे हैं; यह नए देशों में चल रहे आंतरिक राजनीतिक समेकन के महत्वपूर्ण उपाय का परिणाम है, शक्ति समीकरणों के संतुलन में बदलाव और अफगानिस्तान में अशांत स्थितियों से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों की प्रतिक्रिया है, जो मध्य एशियाई देशों के साथ आसानी से सुलभ सीमा और जातीय समुदायों को साझा करती है। मध्य एशियाई नेता हमेशा नायक (ओं) से सावधान रहे हैं और उनके रिश्तों की विविधता उनके प्रबंधन में उनकी गतिशीलता को बढ़ाती है। निम्नलिखित चर्चा से व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में एससीओ की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी।

शीत युद्ध के तत्काल बाद, पश्चिमी यूरोपीय संस्थानों की ओर काफी गर्मजोशी थी, जिसके कारण सम्मेलन में शामिल होने वाले देश यूरोप में सुरक्षा और सहयोग में शामिल हो गए।[12] (1995 में ओएससीई के रूप में "संगठन" में रूपांतरण से पहले), नाटो की शांति के लिए प्रोग्राम में भागीदारी[13] (पीएफपी, 1994), और नाटो-संबद्ध यूरो-अटलांटिक भागीदारी परिषद[14] (1997) सोवियत के बाद के क्षेत्र में रूस के नेतृत्व वाले संस्थान स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस, 1991) , "ताशकंद संधि" या सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ, 1992), यूरेशियन आर्थिक समुदाय (2000), और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू, 2015)थे , जिनकी सदस्यता रूस और संबंधित देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति के आधार पर बदलती रही। स्वतंत्रता के समय, कई मध्य एशियाई देश आर्थिक सहयोग संगठन (ईसीओ , 1985) में शामिल हुए। एक अन्य संगठन जिसमें कई देश शामिल हुए, वह है कजाकिस्तान-द्वारा पहल किया गया एशिया में बातचीत और विश्वास-निर्माण(सीआईसीए, 1999) पर सम्मेलन। 2002 में कुवैत में "अनंतिम" सचिवालय के साथ स्थापित एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) तंत्र में, चीन (2002), भारत (2002), पाकिस्तान (2002), कजाकिस्तान (2003), रूस (2005), ताजिकिस्तान (2006), उज़बेकिस्तान (2006), और किर्गिस्तान (2008) जुड़ गए हैं और यह तंत्र व्यापार और वित्त, कनेक्टिविटी, सतत और समावेशी विकास, और सांस्कृतिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए शिखर/मंत्रिस्तरीय स्तर पर मिलता है। टोक्यो में मुख्यालय के साथ 2016 में स्थापित एशिया परिषद में भी सभी मध्य एशियाई राज्य, जिसमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है, एशिया में सहयोग और सुरक्षा में चुनौतियों का सामना करने के लिए इसके सदस्य हैं। तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र का एकमात्र देश था जिसने स्थापना के बाद से तटस्थता की नीति घोषित की और - भले ही असंगत रूप से - इनमें से अधिकांश संगठनों की सदस्यता से दूर रहा ।

"शंघाई भावना"

जैसे-जैसे यूरेशियन हर्टलैंड में चीनी प्रभाव बढ़ता गया, वैसे-वैसे चीन से संचालित संस्थानों और द्विपक्षीय रिश्तों की भू-राजनीतिक प्रमुखता इस भीड़-भाड़ वाली जगह पर भी बढ़ती गई, भले ही रूसी सामरिक मौजूदगी क्षीण ना हुई हो। अमेरिकी सैन्य मुखरता (1995 का ताइवान जलडमरूमध्य संकट) की प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ किया गया, "शंघाई भावना", आपसी विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर "सहयोगात्मकता" के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के

परिणामस्वरूप एससीओ की स्थापना हुई, जो इसकी "सुरक्षा पर नए आउटलुक" और "सामंजस्यपूर्ण विश्व" का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था, संगठन के लिए "कम कानूनी और अधिक प्रामाणिक" आधार पर बल के साथ नरम भू राजनीतिक संतुलन का अभ्यास कर रहा था।[15] 1990 के दशक के मध्य के बाद से, झिंजियांग के पास-पास संवेदनशील परिधि पर सुरक्षा स्थिति और देशों में राजनीतिक स्थिरता में अपनी मजबूत रुचि के अलावा, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के काफी हाइड्रोकार्बन संसाधनों और साथ ही निर्यात स्थलों के रूप में मध्य एशियाई बाजारों के आकर्षण ने उन्हें एक उत्साह दिया। एससीओ ने इन देशों के साथ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के पैटर्न पर अद्वितीय चीनी लाइसेंस लगाने के लिए एक मंच प्रदान किया। एक अन्य विश्लेषक का कहना है कि चीनी एकेडेमिया और नीति विशेषज्ञ एशिया में अमेरिका की धुरी के बारे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सिल्क रोड पहल[16] के लिए एक प्रमुख औचित्य होने के नाते "एकतरफा में बात करते हैं" ।

एससीओ के विकास के लिए बाहरी प्रेरणा

जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित है, संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ एक रक्षा और सुरक्षा घटक विकसित हुआ है, जिसमें जिसमें 2003 के बाद से रणनीतिक बमवर्षकों[17], के अवसरों पर भागीदारी शामिल है, हालाँकि इसे एक सैन्य ब्लॉक में बनाने की अनुमति नहीं है। रक्षा आयाम के लिए पहल चीन से हुई, जिस पर रूसी पक्ष से कुछ प्रतिरोध हुए जिसने सीएसटीओ को एक संवेदनशील उपाय[18] के रूप में 2002 में एक सैन्य गठबंधन के रूप में बदल दिया। पोलैंड और चेक गणराज्य में प्रस्तावित अमेरिकी मिसाइल रक्षा तैनाती और सुदूर पूर्व में समान प्रणालियों की बात करने के बाद उत्पन्न तनाव के बाद, 2007 के शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ने रूसी आग्रह पर सीएसटीओ के साथ संबंध स्थापित किए जब, सैन्य ड्रिल प्रकार, 'शांति मिशन 2007' - आतंकवाद-रोध से अलग -

अभ्यास शुरू किया गया था।[19] आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ परिधि पर एक सुरक्षा बेल्ट बनाने के लिए, एक अफगानिस्तान संपर्क समूह 2005 में स्थापित किया गया था, 2009 में निलंबित कर दिया गया और 2017 में अफगानिस्तान के लिए ट्रम्प प्रशासन की नई रणनीति के मद्देनजर इसे पुनर्जीवित किया गया; हालाँकि अफगान राष्ट्रपतियों ने 2004 के बाद से, यहाँ तक कि एक पर्यवेक्षक की स्थिति के बिना भी तालिबान हमलों के पुनरुत्थान के बाद, शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, यह समूह अफगानिस्तान में विकास के बारे में परामर्श के लिए एक मंच बना हुआ है, लेकिन वहाँ बातचीत की प्रक्रिया में वार्ताकार के रूप में नहीं।

दक्षिण एशियाई भूराजनीति

यूरेशियन विस्तार से परे व्यापक भूराजनीति, , भारत-चीन संबंधों के सन्दर्भ में भी स्पष्ट है। 2005 में ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के साथ एससीओ में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा मिलने के बाद, नेपाल ने ढाका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) शिखर सम्मेलन में कुछ सप्ताह बाद जोर दिया कि अफगानिस्तान की सदस्यता पर्यवेक्षक के रूप में चीन की स्वीकृति पर निर्भर होगी।[20] इस प्रकार, 2006 में, चीन और जापान को पर्यवेक्षकों के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसने उस संदर्भ को तैयार किया था जिसमें अफगानिस्तान को एक सदस्य[21] के रूप में भर्ती किया गया था; यह वह वर्ष भी है जब चीन भारत-चीन सीमा समझौता पर सहमत राजनीतिक ढांचे से पीछे हट गया; 2014 में सार्क काठमांडू शिखर सम्मेलन में, चीन ने एससीओ की सदस्यता में भारत की रुचि के लगभग समानांतर अपनी सदस्यता में रुचि व्यक्त की।

हालाँकि, सामान्य सहमति है कि एससीओ मंचों पर विवादास्पद मुद्दों से बचा जाना चाहिए, अंतर-राज्य तनाव जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और चीन के बीच तनाव-भरे संबंध संगठन की संस्थागत सामंजस्यता को प्रभावित कर सकते हैं। सितंबर 2020 में, अपने देश के आपत्तिजनक नक्शे पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक अभूतपूर्व प्रदर्शन के कारण एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बाहर चले जाने के लिए विवश किया गया था। जबकि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी सदस्यों के सचेत प्रयासों की आवश्यकता है, इस तरह की गतिविधि को इस तरह के विघटनकारी व्यवहार के पीछे बड़े रणनीतिक इरादे के रूप में ध्यान से देखने की आवश्यकता है: चीन और पाकिस्तान के बीच दीर्घ एलएसी गतिरोध के बारे में समन्वय की एक डिग्री है।

चीन का व्यापक प्रबंधन और एससीओ का आर्थिक सहयोग आयाम

2000 के दशक की शुरुआत से क्षेत्र में चीन द्वारा वित्तीय संसाधनों की भारी तैनाती एक प्रमुख रणनीतिक गतिविधि है। अपने द्विपक्षीय संबंधों में चीन को महत्वपूर्ण लाभ देने के साथ-साथ इसने एससीओ के विकास को भी आकार दिया है। 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव'(बीआरआई) के तहत पश्चिमी यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के माध्यम से ओवरलैंड कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के विकास ने 'सिल्क रोड' के सामान्य नाम के तहत मिश्रित शीत-युद्ध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना की है; अधिकांश एससीओ अवसंरचना परियोजनाएँ चीन द्वारा वित्त पोषित हैं। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का एक अलग पहलू यह है कि एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) जैसी पहले की चीनी पहलों के विपरीत, मध्यस्थता मंचों सहित कार्यान्वयन और वित्तपोषण संस्थान, बिना किसी विदेशी सहयोग के चीनी हैं। विचारपूर्वक नीति के रूप में, एससीओ ढांचे के भीतर आर्थिक सहयोग का पैमाना चीन के द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों से तुलना करने योग्य नहीं है; 2004 से, संयुक्त ऊर्जा परियोजनाओं ("ऊर्जा क्लब") जैसे क्षेत्रों में

एससीओ सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए योजनाएँ तैयार की गई हैं। जल संसाधनों का संयुक्त उपयोग, और पश्चिमी वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता को कम करने के लिए एक बैंकिंग प्रणाली । एससीओ ढांचे के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यापार और अर्थव्यवस्था पारगमन और अन्य बुनियादी ढांचे, कृषि, आईटीसी और तकनीकी आधुनिकीकरण के विकास को कवर करते हैं। नवंबर 2016 में पहली बार, बिश्केक (किर्गिस्तान) शासनाध्यक्षों ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, वित्त और बैंकिंग सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में 2017-21 के लिए परियोजना लिस्टिंग के लिए सहमति व्यक्त की।

“कार्यों का विभाजन” और इनका औचित्य

इस तरह के क्षेत्रीय संस्थागत विकास ने रूस और चीन के बीच एक प्रकार के कार्य के विभाजन को, पहले के लिए एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में, और बाद वाले के लिए क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए लोकोमोटिव के रूप में, प्रतिनिधित्व करना शुरू किया; फिर भी ‘कार्यों का विभाजन’ स्वाभाविक रूप से अस्थिर रहता है क्योंकि प्रत्येक, क्षेत्रीय आर्थिक नीतियों में स्पष्ट रूप में शक्ति समीकरण के मौजूदा संतुलन पर प्रभाव डालता है। चीनी राष्ट्रपति ने 2006 में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के विचार का प्रस्ताव किया है और रूसी राष्ट्रपति ने ईएईयू को स्थापित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के अलावा तीन एससीओ सदस्य देश शामिल हैं।

प्रत्येक शक्ति की आर्थिक प्राथमिकताओं को बड़े सूक्ष्म तरीके से देखा जाता है, हालाँकि; राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने 2018 में क़िंगदाओ शिखर सम्मेलन भाषण में, "बेल्ट एंड रोड सहयोग को निरंतर (ता) आगे बढ़ाने के लिए हमारे संबंधित विकास रणनीतियों की संपूरकता को बढ़ाने की बात कही।"[22] जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने उसी शिखर सम्मलेन में, "कई एकीकरण पहलों" का उल्लेख करते हुए "ईएईयू और चीन के बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम के माध्यम से" समन्वय में वृद्धि पर जोर दिया।[23] मध्य एशियाई देश फिर भी किसी भी संयोजन में इस तरह के समन्वय के बारे में सतर्क रहते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में "विभाजन" बाद के पैराग्राफ में कवर किया गया है।

केन्द्रीय एशियाई देशों ने अखिल-क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की

मध्य एशियाई गणराज्यों ने भी अपनी आजादी के बाद से क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रति ढुलमुल कदम उठाए हैं।[24] तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर, एक मध्य एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1992 में एक साझा बाजार और बाद में एक आम आर्थिक स्थान की परिकल्पना के तहत स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के स्तर पर एक इंटर-स्टेट काउंसिल की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसमें, 1997 में ताजिकिस्तान, अपने गृह युद्ध की समाप्ति के बाद शामिल हुआ था। एक मध्य एशियाई आर्थिक समुदाय (सीएईसी) 1998 में स्थापित किया गया था और 2002 में एक केंद्रीय एशियाई सहयोग संगठन (सीएसीओ); संगठन का विलय 2005 में रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ हुआ था, जिसमें से 2008 में अंतर-क्षेत्रीय रणनीतिक परिवर्तनों' के कारण उज्बेकिस्तान निकल गया था: अंतर-क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ सामाजिक-आर्थिक एकीकरण में एक प्रमुख अवरोधक रही हैं जो हालाँकि एक मजबूत सोवियत विरासत है। उज़बेकिस्तान में नए राष्ट्रपति द्वारा पद सँभालने के साथ, 2016 से मध्य एशियाई राष्ट्रपतियों की नियमित बैठकें शुरू हो गई हैं।

"सी5+1" संवाद

यद्यपि क्षेत्रीय संगठनों के आयामों को नहीं मानते हुए, पाँच मध्य एशियाई देशों और कुछ प्रमुख अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कई संवाद प्रक्रियाएं हैं; ये "सी 5 + 1" संवाद भी राजनीतिक अभिसरण और सहयोग के लिए दिशा प्रदान करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। सबसे पहले देशों में जापान के साथ, एससीओ के व्यापक अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के साथ मेल खाते हुए, और दक्षिण कोरिया । यूरोपीय संघ (ईयू) भी ऐसी प्रक्रिया में भाग लेता है। ऐसा ही अमेरिका 2015 से करता है; अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका "मध्य एशिया के लोगों के साथ मजबूत, संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के रूप में उनके विकास के समर्थन में उनके करीबी दोस्त और भागीदार के रूप में खड़ा है" [25] भारत ने 2019 में अपनी प्रक्रिया शुरू की। हालाँकि चीन के पास बीआरआई और 2012 से आर्थिक सहयोग के अन्य रूपों पर केंद्रित एक ऐसा मंच है, इसने जुलाई 2020 में विदेश मंत्री स्तर पर एक और मंच लॉन्च किया। पहले से ही, अमेरिका और चीन दोनों ने अपने-अपने संबंधों की भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए अपनी "आभासी" बैठकें की हैं क्योंकि देश कोरोनोवायरस महामारी के संभावित अस्थिर प्रभाव का सामना कर रहे हैं।

मध्य एशिया में वर्तमान रणनीतिक परिदृश्य

मध्य एशियाई क्षेत्रीय स्थिति काफी हद तक स्थिर रहती है, लेकिन सभी राज्य समय-समय पर घरेलू तनावों का अनुभव करते हैं जो क्षेत्रीय संस्थानों के विकास को भी प्रभावित करते हैं। विभिन्न देश अपने प्रकार के राजनीतिक उत्तराधिकार या समेकन का अनुभव कर रहे हैं: उज़बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान दोनों को एक सफल राजनीतिक उत्तराधिकार मिला है और रूस में मई 2020 के जनमत संग्रह ने राष्ट्रपति पुतिन की शक्ति को मजबूत किया है। वर्तमान में चल रहे कोविड-19 संकट के विघटनकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप उनकी भूमिगत राजनीतिक अव्यवस्थाएँ फिर भी बढ़ रही हैं। भले ही अधिकांश मध्य एशियाई देश इसकी गंभीरता को कम करके रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव ने इन देशों में घरेलू राजनीतिक नाजुकता के कारण भू-राजनीतिक प्रवाह को प्रेरित किया है। अधिकांश देश कज़ाकिस्तान, रूस, और अन्य यूरेशियाई देशों में अपने प्रवासियों से बाहरी प्रेषण पर निर्भर हैं, इसके अलावा जिंसों पर निर्भर हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन, निर्यात भी शामिल हैं, जो उनकी माँग की गिरावट के कारण काफी कम हो गए हैं। आर्थिक विकास या तो सपाट है या नकारात्मक। इन देशों में अधिकांश ऋण चीनी बैंकों के स्वामित्व में है और वे, चीनी सरकार से, उच्च ब्याज दरों को ले कर उन ऋणों के पुनर्गठन के लिए संपर्क कर रहे हैं; चीन के पास मोलभाव की मज़बूत शक्ति होने के कारण, इन ऋणों का उपयोग राष्ट्रीय संपत्तियों जैसे खनन और गैस अन्वेषण अधिकार, में संपार्श्विक को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, संबंधित देश के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों में इस तरह का फायदा उठाया जा रहा है।

चीनी सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि महामारी के घरेलू आर्थिक प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर बीआरआई कार्यक्रम रुक गया है। यहाँ तक कि चीनी सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए क्षेत्रीय सरकारों को सहायता प्रदान की है

और इस के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को भी खोला है, चीन के खिलाफ आक्रोश केवल उसके आर्थिक वर्चस्व के कारण ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसकी कूटनीति में हाल की अधिक आक्रामकता के कारण भी बढ़ रहा है। चीनी दूतावास की कज़ाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए जुलाई 2020 में सार्वजनिक चेतावनी, जो एक "अज्ञात निमोनिया" के प्रकोप के खिलाफ थी, जो कोविड -19 की तुलना में अधिक घातक था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मौतें हुईं, कज़ाखस्तान की सरकार के साथ ठीक नहीं रही; कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, और ताजिकिस्तान में बड़े सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें शिनजियांग प्रांत के ज्यादातर उइगर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मध्य एशियाई देशों के नागरिक भी बड़े पैमाने पर नजरबंद में शामिल थे।[26] इसी तरह का रुख चीनी मीडिया की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि रूस, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान में गैर-इरादतन क्षेत्रीय दावों को पुनर्जीवित कर रहा है, भले ही सीमाओं पर चीन द्वारा सफलतापूर्वक बातचीत की गई हो। अफ़गानिस्तान में बढ़ती तरलता की स्थिति सीमावर्ती मध्य एशियाई देशों के लिए भी चिंता का विषय है जो संभावित रूप से आरोपित अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के तत्वों और चीन से सुरक्षा के खतरे को बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनमें से कई उज्बेक, ताजिक और उइगर हैं। मई 2020 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के वरिष्ठ नेताओं ने नियमित रूप से अलकायदा के नेताओं के साथ अमेरिका के

साथ उनकी बातचीत के बारे में परामर्श किया है और उत्तरवर्ती ने उनके समझौते का स्वागत किया है।[27] **यहाँ तक कि** रूस और चीन दोनों वर्तमान शांति प्रक्रिया के समर्थक हैं, बावजूद इसके कि इसके अंतिम परिणाम के निहितार्थ के बारे में स्पष्टता नहीं है**,** दोनों के बीच 'कार्यों के विभाजन' का एक बखेड़ा ताजिक-अफगान और अफगान-चीन सीमाओं पर अपनी-अपनी रक्षा-सह-खुफिया सुविधाओं की स्थापना के साथ उभर रहा है; चीन, ताजिक सशस्त्र बलों को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और उनके साथ संयुक्त प्रशिक्षण भी कर रहा है।

मध्य एशिया में एससीओ की प्रमुखता

बदलती हुई भूराजनीतिक गतिशीलता के प्रभाव में बहुपक्षीय तंत्रों को आकार देने का उपरोक्त विवरण एससीओ के संस्थागत डिजाइन में एक अंतर्दृष्टि देता है। एक कमजोर संगठन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए संस्थागत मानदंडों को विकसित करने के लिए छोटे सदस्य देशों के लिए एक साझा मंच की पेशकश करते हुए बड़ी शक्तियों को अपने द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय परिवेश को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त बड़ा स्थान प्रदान करता है। मध्य एशियाई देशों के साथ सी5+1 संवाद प्रारूप का चीनी उपयोग अपने अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के प्रति दृष्टिकोण के अनुरूप है, जबकि यह परियोजनाओं और अन्य निवेशों के वित्तपोषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है; इसलिए भी, निकटवर्ती देशों के साथ उसके आर्थिक संबंधों का स्वरूप, ऋण, व्यापार-मौके, और बुनियादी ढांचे के पुनरभिविन्यास के माध्यम से उत्तरार्द्ध की गहरी निर्भरता द्वारा संचालित किया जा रहा है। सी5+1 प्रारूप संपूर्ण सरकारी-से-सरकारी संबंधों में अखिल मध्य एशियाई सहयोग को विकसित करने के लिए बाहरी शक्तियों के हित को दर्शाता है लेकिन यह अभी भी एक संवाद प्रक्रिया ही है और एससीओ का एक प्रतिस्थापन नहीं है।

एक प्रमुख चीनी शहर के नाम धारक और अपने बढ़ते हुए बहुपक्षीय उभार के शुरुआती चरण में देश के पहले महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कदम के साथ पहचाना

गया यह संगठन चीन के लिए एक स्थायी गुणवत्ता है और दूसरों के लिए उपयोगी है। एक वैकल्पिक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की एक बड़ी योजना का हिस्सा, इसकी जटिल संस्थागत संरचना पूरे यूरेशियाई हृदय क्षेत्र को कवर करने की क्षमता के साथ इसे मध्य एशिया के लिए एकमात्र संगठन बनाती है। यह सदस्यता, भौगोलिक स्थान और गैर-अंतर्राष्ट्रीय देशों / बहुपक्षीय संस्थानों की संख्या को अपने वार्ताकारों के रूप में बढ़ा रहा है। इसलिए, यह एक सक्रिय भारतीय कूटनीति और मध्य एशियाई देशों के साथ गहरे जुड़ाव के लिए एक अनिवार्य मंच बना हुआ है।

मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक हित

भारत के रणनीतिक हित

इसके ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों और सोवियत काल के बाद से सद्भावना कायम करने के अलावा, दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए रणनीतिक घटनाक्रम के निहितार्थ, हाल के दिनों में भारतीय सुरक्षा योजनाकारों द्वारा उत्सुकता से अनुगमन किए गए हैं; विस्तार से, मध्य एशियाई शक्ति संतुलन ने हमेशा उन्हें दिलचस्पी दी है। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और रणनीतिक रूप से विघटनकारी घटनाओं की परिणामी हिदायत और सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद दक्षिण एशिया के लिए भी रणनीतिक परिदृश्य मूलरूप से बदल गया है।

जैसा कि क्षेत्र के सोवियत के बाद के इतिहास से पता चलता है, मध्य एशिया के घटनाक्रम अफगानिस्तान को और विपरीततः प्रभावित करते हैं। यद्यपि मध्य एशियाई घटनाक्रमों में तालिबान को दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वहाँ की अशांत परिस्थितियों ने इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों के लिए एक आश्रय प्रदान किया - तालिबान की मिलीभगत के साथ या अन्यथा - जो इन देशों में राजनीतिक व्यवस्था को उलटना चाहते थे; इनमें से कई भारत के लिए चिंता के कट्टरपंथी तत्वों के साथी यात्री हैं। यह एक ऐसा खतरा है जो, अगर अधिक नहीं तो, हमेशा की तरह शक्तिशाली बना हुआ है, यह देखते हुए कि उनमें से अधिकांश सीरिया और इराक में पेशेवर सेनाओं के खिलाफ युद्ध के माध्यम से कठोर हो चुके हैं। मध्य एशियाई देशों ने पहले, अपनी सोवियत के बाद की यात्रा के दौरान इन चुनौतियों का सामना किया है और इन चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार है; अतिव्यापी जातीय समुदायों को देखते हुए, अर्थात्, ताजिक, उज़बेक और तुर्कमेन, सामरिक रुझानों में पारस्परिक रूप से मजबूत स्वरुप है और अगर अफगानिस्तान में चल रही राजनीतिक प्रक्रिया में हाई प्रोफाइल बड़ी शक्ति चालों और पलात्वरों के बीच कुछ हद तक अनदेखी हुई, मध्य एशियाई देश भी हितधारक हैं ।

भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच हितों का अभिसरण

यद्यपि अपने एससीओ दायित्वों की घोर उपेक्षा में, पाकिस्तान द्वारा भूमि के उपयोग से इनकार करने के कारण अक्षम भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक और परियोजना सहयोग की काफी संभावनाएँ नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) और चाबहार (ईरान) के माध्यम से मध्य एशिया के साथ-साथ अफगानिस्तान तक ओवरलैंड कनेक्टिविटी का विकास भी इसे दोनों के लिए रणनीतिक महत्व के रूप में देखा जाता है। मध्य एशिया प्राकृतिक संसाधनों जैसे हाइड्रोकार्बन और खनिजों से समृद्ध है, जिनका इसके विचार में अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इनकी आईटी

क्षमताओं और विमानन संपर्क का लाभ उठाकर इन देशों के साथ चौतरफा आर्थिक सहयोग को विकसित करने की काफी गुंजाइश है; इस प्रकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, सेवाओं और संस्कृति में मजबूत संबंध विकसित किए जा सकते हैं। उनके प्रति अपने गैर-अधिशासी सम्बन्ध और गैर-वैचारिक दृष्टिकोण को मान्यता देते हुए, मध्य एशियाई नेता क्षेत्र में व्यापक भारतीय उपस्थिति और घनिष्ठ सुरक्षा और सैन्य संबंधों का स्वागत करते हैं; हालाँकि, वे सचेत रहते हैं कि इससे चीन और पाकिस्तान के साथ कहीं किसी प्रकार की सामरिक प्रतिद्वंद्विता न हो जाए , हालाँकि उन्हें यह भी उम्मीद है कि एससीओ के संस्थागत ढांचे के भीतर उनकी राजनयिक बातचीत संभवत: उनके संबंधित द्विपक्षीय संबंधों में भी कमी ला सकती है। उल्लिखित बाधाओं के कारण संबंधों के अवमूल्य पर होने के साझा अहसास के बावजूद, दोनों पक्ष आश्वस्त हैं कि उनके मजबूत संबंध उनकी आम चुनौतियों का सामना करने में उनके रणनीतिक हितों की रक्षा करने में मदद करेंगे।

भारत-एशिया के संबंध की सीमा

गोर्बाचेव के पेरेस्त्रोइका के दौरान मध्य एशिया में राजनीतिक घटनाओं की गति तेज हुई और सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारत नए स्वतंत्र मध्य एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था

इसके साथ ही, मौलिक रूप से परिवर्तित लेकिन अनिश्चित परिस्थितियों में द्विपक्षीय संबंधों की सीमा का विस्तार करने के लिए उच्च-स्तरीय यात्राओं का त्वरित आदान-प्रदान था । चल रहे सहयोग के क्षेत्रों में क्रेडिट की रियायती लाइनों, निवेश, पारगमन गलियारों, ऊर्जा (2008 में भारत की एनएसजी छूट के बाद कज़ाकिस्तान और उज़बेकिस्तान से यूरेनियम की आपूर्ति), शिक्षा और प्रशिक्षण, सैन्य परिवहन की आपूर्ति और इन-फ्लाइट ईंधन भरने वाले विमान (उज़बेकिस्तान से), संयुक्त सैन्य अभ्यास (कजाकिस्तान और किर्गिस्तान), आतंकवाद विरोधी और नशीले पदार्थों के संवाद आदि के रूप में विकास सहयोग शामिल हैं। प्रधान मंत्री मोदी के पहले पाँच साल के कार्यकाल के दौरान, ' कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी' को 2015 में सभी पाँच मध्य एशियाई देशों की यात्रा के साथ मजबूत किया गया; भारत, व्यापार और पारगमन की सुविधा के लिए अश्गाबात समझौते में शामिल हो गया, जिसमें ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान शामिल हैं । इसने 2019 में विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत-मध्य एशिया वार्ता शुरू करने की पहल भी की। आम हित के रणनीतिक मुद्दों के अलावा, इस वार्ता का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना है। सद्भावना की पारंपरिक निधि पर आधारित, ये संबंध, फिर भी लगातार बढ़े हैं, यहाँ तक कि दोनों पक्ष यह मानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों को अभी भी कवर करने की आवश्यकता है, विशेषकर वर्तमान बदली परिस्थितियों में।

भारत और एससी ओ

एससीओ की भारत से उम्मीदें

एससीओ के महासचिव ने जून 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार[28] में कहा कि भारतीय भागीदारी के साथ, "क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियों को आकार देने के लिए एससीओ की भूमिका, सुरक्षा और सतत विकास को

सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत हुई है": "एससीओ के राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय व्यवहार यूरेशिया के भूस्थैतिक विकास की रूपरेखा हैं।" भारत को "एक गतिशील रूप से विकासशील आर्थिक शक्ति, एक बड़े राज्य" के रूप में वर्णित करते हुए, प्रधान मंत्री मोदी की एससीओ देशों की यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों के विकास में बल्कि एससीओ के भीतर सहयोग को मजबूत करने के लिए भी सहयोग दिया है। भारत के विशाल बाजार के साथ सहयोग और विदेशी निवेश की क्षमता के लिए दो-तरफा अवसर हैं। उन्होंने भारतीय शक्तियों, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में - विशेष रूप से वैश्विक कोविड-19 संकट के दौरान , परिवहन अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय पारगमन गलियारों के लिए योगदान, डिजिटलाइजेशन और नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों में भागीदारी और सस्ती सौर ऊर्जा के विकास के बारे में बताया। भारत एससीओ के आतंकवाद-रोधी तंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उन्होंने अफगान शांति प्रक्रिया पर प्रधान मंत्री मोदी के विचारों के साथ सहमति व्यक्त की। हाल ही में एक सम्मेलन (2 सितंबर 2020) में, उन्होंने विशेष रूप से एससीओ सदस्य देशों में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए क्षमता निर्माण में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

भारत की भूमिका

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत विभिन्न संगठनों का सदस्य है जिसमें मध्य एशियाई देश शामिल हैं। एससीओ का, हालाँकि, इस क्षेत्र में एक मजबूत आधार है। अन्य संवाद चैनलों के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि भारत इस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ-साथ अपने क्षेत्रीय प्रभाव को भी बढ़ाए। जैसा कि संगठन ने, तालिबान पर अमेरिकी हमले और अमेरिकी सैन्य अभियानों के प्रभाव के कारण उत्तरवर्ती के पुनरुत्थान के मद्देनजर इस क्षेत्र में अधिक से अधिक भू-राजनीतिक प्रमुखता हासिल की, भारत, 2005 में एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ और बोलने और अवलोकन करने - शिखर स्तर पर बैठकों में साइडलाइन/स्वगत कथनों पर शामिल होने में सक्षम था, लेकिन निर्णय लेने में भाग नहीं ले सका।

जुलाई 2015 में, एससीओ ऊफ़ा (रूस) शिखर सम्मेलन ने भारत को अपनी आब्जर्वर की स्थिति से अपग्रेड करके सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। जून 2016, में इसके ताशकंद (उज्बेकिस्तान) शिखर सम्मेलन में, भारत ने अनुक्रमिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रूपरेखा दायित्व के प्रारंभिक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद इसने आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद के मुकाबले पर इसके चार्टर और शंघाई सम्मेलन सहित 34 एससीओ समझौतों को स्वीकार किया; सदस्य के रूप में प्रवेश पर, भारत ने अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को बीजिंग में इसके सचिवालय सहित विभिन्न एससीओ अंगों में भेजा है।

प्रधान मंत्री मोदी की एससीओ के प्रति नीति की अभिव्यक्ति

प्रधान मंत्री मोदी ने एससीओ के अस्ताना शिखर सम्मेलन में, भारत के सदस्य बनने पर, अपने भाषण[29] में कहा कि संगठन वैश्विक जनसंख्या का 42%, इसके

सकल घरेलू उत्पाद का 20% और भूमि द्रव्यमान का 22% का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने सदस्य देशों के साथ भारत के राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के मुख्य स्तंभों के रूप में "पारस्परिक विश्वास और सद्भावना" पर प्रकाश डाला जहाँ इसकी एससीओ सदस्यता ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, खनिज, क्षमता निर्माण, विकास साझेदारी और व्यापार और निवेश के पहले से मौजूद क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी। क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी-संबंधी सहयोग में भारत की भागीदारी पर इशारा करते हुए, उन्होंने जोर दिया - बीआरआई और सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे) की परोक्ष आलोचना में - भारतीय दृष्टिकोण की विशेषता "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान" के रूप में और उनकी “समावेशिता और स्थिरता” में भी है। उन्होंने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में एससीओ की संभावित भूमिका को रेखांकित किया और वैश्विक संदर्भ में पर्यावरण परिवर्तन पर संगठन के फोकस का सुझाव दिया। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एससीओ के प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने सदस्य देशों के कट्टरपंथीकरण, आतंकवादियों की भर्ती, उनके प्रशिक्षण या वित्तपोषण की चुनौतियों पर समन्वित प्रयासों की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया। 11 जून 2018 को अपने एससीओ क़िंगदाओ (चीन) शिखर सम्मेलन भाषण[30] में, "पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में", उन्होंने कौशल विकास, क्षमता-निर्माण और कई क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास में सहयोग की बात कही, जो उन्हें संक्षिप्त रूप में सिक्योर कहते हैं (हमारे नागरिकों की सुरक्षा, सभी के लिए आर्थिक विकास, इस क्षेत्र को जोड़ने, हमारे लोगों को एकजुट करने, संप्रभुता और अखंडता के लिए सम्मान, और पर्यावरण संरक्षण)।

भारत और शंघाई सहयोग संगठन: तीन निबंध

उसी समय, उन्होंने अफगानिस्तान के लिए एससीओ के संपर्क समूह में भारत की सक्रिय भूमिका की पेशकश की। जून 2019 में एससीओ बिश्केक (किर्गिस्तान) शिखर सम्मेलन में, प्रधान मंत्री ने एससीओ गतिविधियों में भारत के "सकारात्मक योगदान" का उल्लेख[31] किया और संक्षिप्त रूप में हेल्थ HEALTH (स्वास्थ्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, वैकल्पिक ऊर्जा, साहित्य और संस्कृति, आतंकवाद मुक्त समाज, और मानवीय सहयोग)) में सहयोग के विभिन्न विशिष्ट मुद्दे-आधारित क्षेत्रों का सुझाव दिया। उन्होंने सकारात्मक रूप से "एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह की आगे की कार्रवाई के लिए रोडमैप" नोट किया।

विदेश मंत्रालय द्वारा रेखांकित सहयोग कार्यक्रम

विदेश मंत्री ने 22 मई 2019 को विदेश मंत्रियों की परिषद की बिश्केक बैठक में अपने हस्तक्षेप[32] में "अशांत वैश्विक परिदृश्य" के बावजूद सदस्य राज्यों के बीच विस्तृत होते पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने पर्यटन के लिए एससीओ की संयुक्त कार्य योजना (2019-20) को, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलों के लिए, जो "समावेशी, टिकाऊ, पारदर्शी हैं" और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों (का सम्मान)" हैं, पर्यावरण संरक्षण पर एससीओ कार्य योजना (2019-21) के लिए भारतीय प्रतिबद्धता का उल्लेख किया और कृषि, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वित्त और अक्षय ऊर्जा में भारतीय विशेषज्ञता को साझा करने की पेशकश की। उन्होंने यूएनएससी (2021-22 और 2027-28) की गैरस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों की उम्मीदवारी के लिए एससीओ समर्थन की उम्मीद की जैसा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और यूएनएससी के व्यापक सुधारों की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया। श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमले और पुलवामा हमले के "अभी भी कच्चे" घावों को याद करते हुए, उन्होंने आरएटीएस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विचारों का आह्वान किया। उन्होंने एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह की भूमिका का और कार्रवाई

के लिए रोडमैप को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का समर्थन किया । हाल ही में एक सम्मेलन (2 सितंबर 2020) में, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) ने कहा[33] भारतीय फोकस, एमएसएमई में आर्थिक सहयोग की सुविधा, कृषि-प्रसंस्करण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फार्मास्यूटिकल्स और हरित प्रौद्योगिकी आदि के अलावा, स्टार्ट-अप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर है; भारतीय योजनाओं में साझा बौद्ध विरासत, रूसी और चीनी में भारतीय क्षेत्रीय क्लासिक्स का अनुवाद और युवा संपर्कों को मजबूत करना शामिल है।

एससीओ की वर्तमान व्यस्तताएँ

अनुलग्नक-बी (पृष्ठ 33) में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न समझौता ज्ञापनों को सूचीबद्ध किया गया है, जो एक सक्रिय उच्च-स्तरीय भागीदारी को इंगित करता है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित एससीओ की बैठकों में अपने सदस्य देशों को शामिल करने वाली अंतर-सरकारी गतिविधियों की एक विशाल श्रेणी में बैठकें शामिल हैं। ये आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया, पर्यावरण, संस्कृति और पर्यटन और एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की बैठकें शामिल हैं। ये सूची सदस्य राज्यों के बीच व्यापक सहयोग का संकेत है। भारत और चीन के बीच हालिया तनाव के संकेत में, पूर्व ने 'शांति मिशन अभ्यास' के लिए सैन्य टुकड़ी भेजने के खिलाफ फैसला किया, जो कि कजान में रूसी नेतृत्व में कोविड से संबंधित सावधानियों के कारण बुलाई गई, लेकिन वास्तव में चीनी दल के साथ भाग लेने के प्रति अनिच्छा के कारण। हालाँकि, भारतीय रक्षा मंत्री ने मॉस्को में एससीओ रक्षा मंत्रियों की व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया और उत्तरवर्ती के आग्रह पर अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई।

मॉस्को में एससीओ बैठक के मौके पर भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी हुई। अपने कई मंचों के कारण, एससीओ चीन और पाकिस्तान सहित सदस्य देशों से सशस्त्र बलों और खुफिया सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखों के लिए, जब और जिस तरह की आवश्यकता होती है, तब बैठकों के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।

सुझाए गए दृष्टिकोण

कोविड- विकसित घटनाक्रमों, वैश्विक अनिश्चितताओं, विभिन्न देशों में नेतृत्व पर घरेलू दबाव, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर द्रव क्षेत्रीय भू-राजनीति को देखते हुए संगठन के लिए भारतीय दृष्टिकोण इसके आसन्न अध्यक्षता के मद्देनजर संगठन को एक निश्चित अंशांकन की आवश्यकता पड़ सकती है, यहाँ तक कि भारतीय कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी। इस वर्ष नई दिल्ली में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की बैठक में एक विस्तृत रूप से विस्तृत एजेंडा पेश करने के लिए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो उस समय तक फलने-फूलने के लिए लिया जा सकता है जब तक भारत राज्य प्रमुखों की परिषद के अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। एससीओ विकास की रणनीति, 2025 तक, क्षेत्रीय "शांति, सुरक्षा और स्थिरता" को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने कामकाज के सभी पहलुओं को शामिल करती है, जिसकी सीमा में राजनीतिक, सुरक्षा (आतंकवादियों और आतंकी वित्तपोषण के प्रत्यर्पण सहित), आर्थिक और व्यापार सहयोग, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग होता है; महत्वपूर्ण रूप से, यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VIII के तहत स्वयं के लिए एक भूमिका की परिकल्पना करता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में क्षेत्रीय संगठनों की भागीदारी से संबंधित है।

राजनीतिक: एससीओ के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का व्यापक राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण निम्नलिखित पंक्तियों के साथ हो सकता है:

चरम वैश्विक और घरेलू तरलता राष्ट्रीय नेताओं को बाहरी प्रतिरक्षा का सहारा लेने के लिए विवश करती है। कम से कम निकट अवधि में कोविड प्रेरित वित्तीय बाधाओं के कारण, भारत को अन्य देशों, विशेष रूप से चीन के साथ डॉलर के लिए डॉलर का मिलान नहीं करना पड़ता है लेकिन मध्य एशियाई नेताओं के हित के क्षेत्रों में सहयोग की निरंतरता प्रदर्शित करना होता है।

- मध्य एशियाई देशों के साथ चीन के संबंध उत्तरवर्ती के नुकसान के लिए और भी अधिक विषम हो गए हैं, उनके आपसी अविश्वास के निकट भविष्य में बेहतर होने की संभावना नहीं है और न ही आर्थिक सहयोग का स्तर उत्तरवर्ती की स्थिति में किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन का प्रभाव करेगा, चीन की क्षमता अपने स्वयं के कोविड से संबंधित आर्थिक संकट के कारण बेअसर होगी, इस तथ्य से अधिक जटिल कि ज्यादातर मध्य एशियाई देश बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में चीन के रू-बरू भारी कर्ज का बोझ रखते हैं। अन्य देशों के साथ सहयोग और धारणा प्रबंधन में एक निश्चित प्रयास के माध्यम से क्षेत्रीय भविष्य की एक वैकल्पिक दृष्टि पेश करने के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं;

इस बड़े बहुआयामी सहयोग को अन्य गैर-शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ भी किया जा सकता है जिनके मध्य एशियाई देशों के साथ सक्रिय सी5 + 1 संवाद संबंध हैं। इस तरह के व्यवहार की आक्रामकता एक स्वरूप का गठन करता है है, जो न केवल भारत के मामले में, बल्कि दक्षिण चीन सागर के अन्य तटीय देशों और अन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट है। छोटे मध्य एशियाई देश भी इस पैटर्न में आ रहे हैं।

आरआईसी की विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक (23 जून 2020) में विदेश मंत्री की टिप्पणी, वर्तमान संदर्भ में नए भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनकी टिप्पणी कि आज की चुनौती है "उनके (अवधारणाओं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मानदंड) अभ्यास के अनुरूप हों " जहाँ "दुनिया की प्रमुख आवाजों को हर तरह से अनुकरणीय होना चाहिए", हर मंच पर दोहराए जाने चाहिए, उपयुक्त शब्दों में, इस बात पर जोर देने के लिए कि बहुपक्षीय संगठन, आज की दुनिया में अपनी अत्यधिक आवश्यकता के बावजूद द्विपक्षीय विवादों के समाधान में आक्रामकता की पुनरावृत्ति द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की सख्त अवहेलना के माध्यम से अपने सदस्यों के बीच विश्वास के विनाश के साथ पनप नहीं सकते । वास्तव में, यह दृष्टिकोण एससीओ के संस्थापक सिद्धांतों के अनुरूप है, विशेष रूप से पहले उद्धृत किए गए एससीओ चार्टर का अनुच्छेद 2 ।

- प्रमुख एससीओ बैठकों की साइडलाइन्स के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श के माध्यम से एक निश्चित दबाव बनाए रखा जा सकता है। उनके अपने मामलों के दोहन में, ऐसे प्रयास रूस प्रतिनिधिमंडल सदस्यों के परामर्श करके किये जा सकते हैं; ईएईयू की सदस्यता की बातचीत में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण से लाभांश प्राप्त होगा, साथ ही यूरेशियन स्थान में रूस समर्थक 'संतुलन' का संकेत भी मिलेगा। एससीओ, राय बनाने के लिए एक

उपयोगी मंच बना हुआ है क्योंकि इसमें सभी प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। एससीओ एनएसए की बैठक में पाकिस्तान का हालिया व्यवहार इस संगठन के कामकाज के प्रति उसके विघटनकारी दृष्टिकोण का संकेत है। हमें इस तरह से जवाब देने की आवश्यकता है ताकि अन्य सदस्य राज्यों, संवाद भागीदारों और पर्यवेक्षकों को इन तरल समय में संगठन की मजबूत प्रभावशीलता के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता के बारे में बता सकें।

- **आर्थिक**

बड़े एससीओ ढांचे के भीतर भारत के आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

हम एससीओ के गैर-पारंपरिक सुरक्षा एजेंडे पर अधिक ध्यान केंद्रित रख सकते हैं, जो कई घरेलू दबावों का सामना कर रहे मध्य एशियाई नेताओं के लिए एक चुनौती भी पेश करता है, जहाँ अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, वर्तमान महामारी के दौरान महत्वपूर्ण, राज्य की नाजुकता में योगदान कर सकते हैं। प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं द्वारा उल्लिखित अधिकांश कार्यक्रमों को इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पुन: पेश किया जा सकता है कि क्या वे शासन से संबंधित हैं, सेवाओं के डिजिटलाइजेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, जल संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली की कमी, मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया और इसी प्रकार के किसी से संबंधित हैं।

क्षमता निर्माण इन सभी कार्यक्रमों के समर्थन में जमीनी स्तर पर सामुदायिक गतिशीलता के रूप में एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। फोकस त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं पर हो सकता है।

- सभी उपयुक्त एससीओ मंचों में, कनेक्टिविटी के मुख्य मुद्दे पर भारतीय दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान और उसके बाद मध्य एशियाई क्षेत्र में भारतीय माल के पारगमन को रोकना भी शामिल है। हमारी कूटनीति को आईएनएसटीसी के एससीओ के पारगमन पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

- भारत को जल्दी से एससीओ के इंटरबैंक कंसोर्टियम में एक संबंधित भारतीय बैंक को नामित करना चाहिए। इस भागीदारी के माध्यम से, हस्ताक्षरित भारतीय योगदान के रूप में विशेष ध्यान दिया जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न आर्थिक सहयोग कार्यक्रम आर्थिक व्यवहार्यता, पारिस्थितिक स्थिरता और पारदर्शिता के मानदंड के अनुरूप हों। यह अधिमानतः कृषि वित्तपोषण, सहकारी बैंकिंग के विशेष अनुभव के साथ एक बैंक हो सकता है, जो गरीब सामाजिक समूहों, एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों की जरूरतों को पूरा कर सकता हो । यह सब एक वैकल्पिक दृष्टिकोण से जोड़ देगा, जिसे प्रधानमंत्री ने जी -20 जैसे अन्य बहुपक्षीय मंचों पर पेश किया है।
- अनिवार्य रूप से, सभी एससीओ सदस्य देशों के बीच मुख्य संबंध, द्विपक्षीय संबंध होने के नाते, भारत इस मंच का उपयोग अपने पैन-मध्य एशियाई सहयोग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। यदि एससीओ बैठकों के साथ समानांतर "सी 5+1" प्रारूप संवाद क्रम में नहीं है, तो एससीओ बैठकों से पहले या बाद में एक अलग सेटिंग - जहाँ, जैसा संभव हो, यह राज्य / सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जा

सकता है। इस तरह की समानांतर प्रक्रियाओं के माध्यम से, सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में एससीओ फोरम की बैठकें, ट्रांस-शिपमेंट और लॉजिस्टिक्स हब जैसे क्षेत्रीय प्रभावों के साथ अखिल-मध्य एशियाई क्षेत्रीय परियोजनाओं या एकल देश परियोजनाओं को अंतिम रूप देने का अवसर प्रदान कर सकती हैं।

धारणा प्रबंधन सहित सांस्कृतिक सहयोग

चीनी 'सॉफ्ट पावर' की कूटनीति अप्रभावी साबित हुई है, मध्य एशियाई देशों के साथ भारतीय सहयोग की प्रकृति की अधिक निवर्तमान बाहरी मीडिया प्रोजेक्शन में काफी संभावनाएँ हैं। मध्य एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर भारतीय दृष्टिकोण के साथ हमारे स्थायी सभ्यतागत संस्कृति संपन्न संबंधों को देखते हुए, इस तरह के मीडिया आउटरीच के बेहतर धारणा प्रबंधन में हमारे प्रयासों का एक सैल्यूटरी प्रभाव होगा। यह अनिवार्य रूप से हमारे टीवी और रेडियो सिग्नलों का बेहतर प्रसार करता है, जिसमें स्थानीय योगदानकर्ताओं की मदद से स्थानीय भाषाओं में विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सामग्री होती है। इस आउटरीच को संयुक्त डिग्रियों सहित संयुक्त रूप से विकसित शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारतीय क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाले एक अधिक आधुनिक आउटरीच को हमारी साझा सभ्यता विरासत के प्रमुख पहलुओं में समुदायों के स्थायी हित में सफलतापूर्वक एंकर किया जा सकता है।

इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रति इन देशों की संवेदनशीलता, भारत के लिए इन समुदायों में आर्थिक और तकनीकी रूप से आधुनिक बनने के लिए एक तैयार ग्रहणशीलता को सुनिश्चित करती है।

आतंकवाद

आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में एससीओ सदस्य देशों और इसकी संरचनाओं के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना, एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ हमारे पेशेवर राजनयिकों की भागीदारी की एक अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है।

- चूंकि आतंकवाद एक संगठन और व्यक्तिगत सदस्य देशों के रूप में एससीओ की समान चिंता है, भारत दक्षिण-पश्चिम एशिया में अल कायदा और आईएसआईएस के बढ़ते खतरे और हक्कानी नेटवर्क के साथ उनके विख्यात संबंधों को उजागर कर सकता है। चूँकि ये तत्व खुद मध्य एशियाई राज्यों के लिए बहुत चिंता का विषय हैं, इसलिए यह दृष्टिकोण पाकिस्तान को बचाव की मुद्रा में डाल सकता है। अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौते को आकार देने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जा रहे उनके निरंतर संपर्क मध्य एशियाई राज्यों के लिए बहुत चिंता का विषय हैं। इस कारक का, आतंक के वित्तपोषण पर पाकिस्तान के निराशाजनक रिकॉर्ड के संयोजन में, इस पर दबाव बनाने और क्षेत्रीय प्रभाव के साथ और इससे भी आगे पाकिस्तान-चीन सांठगांठ के लिए लाभ उठाया जा सकता है। इस कठिन वास्तविकता को, जो मध्य एशियाई और अफगान नेताओं को और अधिक खतरे में डालने वाली है, को एससीओ मंचों और बैठकों / संपार्श्विक बैठकों/स्वगत कथनों में प्रमुख रूप से उठाए जाने की आवश्यकता है।
- हमारी विशिष्ट एजेंसियाँ आरएटीएस गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जिहादी आतंकवादी नेटवर्क का अध्ययन लगभग सभी

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और विश्लेषकों द्वारा किया गया है। भले ही यह एजेंसी भारत के लिए सीमा पार आतंकवाद के संबंध में बहुत मदद नहीं कर सकती है, इसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर डेटाबेस का दोहन किया जा सकता है क्योंकि इनमें से कुछ संगठन सक्रिय रूप से भारत में अपने जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दवाओं की तस्करी और आतंक के वित्तपोषण नेटवर्क के लिए भी यही लागू होगा। भारतीय कूटनीति एफएटीएफ और संयुक्त राष्ट्र 1267 समिति के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकती है।

- आतंकवाद रोधी कार्रवाई के लिए खोजी, अभियोजन पक्ष और विधायी आयामों में भारत की उच्च गुणवत्ता वाली विशेषज्ञता को आरएटीएस और अन्य संबंधित प्लेटफार्मों पर साझा किया जा सकता है।

अफ़ग़ानिस्तान

चल रहे दोहा अफ़ग़ानिस्तान शांति वार्ता में संभावित राजनीतिक समझौते की गुणवत्ता में उनके गहरे रणनीतिक दांव के बारे में सचेत, मध्य एशियाई राज्यों को चिंता है कि उनकी विफलता - या, यहाँ तक कि राज्य पतन - का उस देश में घटनाओं की भविष्य की कार्रवाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, सभी तीन पड़ोसी मध्य एशियाई देशों, अर्थात्, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमाओं के बीच महत्वपूर्ण जातीय लिंक हैं, जो वर्तमान वार्ता प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को काफी हद तक आकार देगा।

इस दृष्टिकोण से, एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह में हमारी सक्रिय भागीदारी और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ इस मुद्दे पर द्विपक्षीय बातचीत एक निश्चित सीमा तक वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय कूटनीतिक क्षमता निर्माण

इस महत्वपूर्ण समय में भारत द्वारा एक प्रभावी भूमिका के लिए, हमारे उद्देश्यों को साकार करने में हमारी कूटनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। एससीओ को आसान समन्वय और तेजी से भारत सरकार की प्रतिक्रिया के लिए रूसी और चीनी भाषाओं के अलावा एक और कामकाजी भाषा के रूप में अंग्रेजी को जोड़ने की आवश्यकता है, जो सरकार के पूरे स्तर पर मजबूत अंतर-एजेंसी तालमेल में मदद करेगी। इस संस्थागत मजबूती में अपेक्षित भाषा कौशल वाले अधिक राजनयिकों और अन्य विषय विशेषज्ञता वाले अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है।

उपसंहारात्मक टिप्पणी

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बढ़ी हुई भूराजनीतिक अनिश्चितता के साथ कोरोनावायरस महामारी के विघटनकारी प्रभाव, जिसमें कुछ हिस्सा चीन की आक्रामकता का था, ने मध्य एशिया में मौलिक रूप से रणनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। भारत की अपनी वित्तीय बाधाओं के बावजूद, इसकी कूटनीति एक निश्चित विचार प्रक्रिया तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, कि मध्य एशियाई क्षेत्र और बड़े पैमाने पर दुनिया में, कोविड के बाद का किस तरह का भविष्य बनाया जा सकता है। एससीओ, अपनी विस्तृत संस्थागत संरचना के कारण, भारतीय कूटनीति के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करता है और इसके आगामी अध्यक्ष-पद को एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जैसा कि मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ-साथ यूरेशियन क्षेत्र में भी अन्य प्लेटफॉर्म हैं, भारतीय

कूटनीति अधिक ठोस प्रभाव के लिए एससीओ के साथ उनका उपयोग कर सकती है। यह कूटनीति के दायरे को व्यापक करता है और, एससीओ के गैर-सदस्य सहित, अन्य शक्तियों से साथ एक निश्चित डिग्री के लिए सामरस्यता की अनुमति देता है।

जैसा कि हाल के रुझानों से संकेत मिलता है, रूस यूरेशिया में एक उपयोगी और इंडो-पैसिफिक में एक संभावित भागीदार बना हुआ है। एक रूसी विश्लेषक ने कहा है कि "चीनी विदेश नीति की अधिक मुखरता, एससीओ के लिए एक मजबूती परीक्षण भी साबित हुई है" जैसा कि उसने रूस और भारत दोनों के लिए एससीओ के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया, जहाँ दोनों को (चीन को) थोड़े वश में करने की जरूरत है"[34]

हमारा बड़ा उद्देश्य एससीओ और अन्य संबंधित संवाद मंचों का उपयोग, स्थायी और समान आर्थिक विकास - इसके वर्तमान "सहयोग मॉडल" से भिन्न -के साथ इस क्षेत्र में अधिक से अधिक स्थिरता को रेखांकित करने के लिए होना चाहिए । भारत की सक्रिय कूटनीति, प्रभावी धारणा प्रबंधन, और क्षेत्र में रुचि रखने वाले अन्य समान सोच वाले देशों के साथ एक निश्चित सहयोगात्मक प्रयास इस तरह की दिशा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जी -20 जैसे अन्य प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय संगठनों की आगामी भारतीय प्रेसीडेंसी के साथ, भारत के पास कोविड के बाद की दुनिया को आकार देने की दिशा में अपने हस्ताक्षर योगदान करने का एक अनूठा अवसर है। □

Endnotes

1. Derek Grossman, *China Will Regret India's Entry Into the Shanghai Cooperation Organization* (24 July 2017), The Rand Blog. rand.org/blog/2017/07/china-will-regret-indiasentry-into-the-shanghai-cooperation.html. Accessed on 31 August 2020. At the 2017 SCO summit (Astana, Kazakhstan) President Putin "welcomed" by name the Prime Minister of India and Pakistan whereas President Xi mentioned tersely about SCO "going to admit India and Pakistan as new member states". At the 2018 SCO summit (Qingdao, China), President Putin said that SCO "has become stronger" with the joining of the two full members whereas President Xi made no mention at all. For the larger SCO debate on membership of India, Pakistan, Iran, and Afghanistan, see Anna Matveeva and Antonio Giustozzi, *The SCO: A Regional Organization in the Making,* Working Paper 39 – Regional and Global Axes of Conflict (London School of Economics, 2008)
2. CSTO members are Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan and observers are Afghanistan and Serbia. See Wikipedia entry on the organization
3. ECO members are Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan and observers are Northern Cyprus, Organization of Islamic Cooperation, Turkic Council And Energy Charter. See Wikipedia entry on the organization
4. CICA comprises 27 countries in Asia, 8 observer states including US, and 5 observer organizations including OSCE and UN. See Wikipedia entry on the organization
5. Wikipedia entry on SCO. Accessed on 23 August, 2020
6. Dilip Hiro, *Shanghai Surprise,* The Guardian (16 June, 2016). theguardian.com/commentisfree/ 2006/jun/16/ shanghaisurprise. Accessed on 29 August, 2020
7. Official SCO website, eng.sectsco.org/about_sco. Accessed on 23 August, 2020
8. Ibid
9. SCO website. web.archive.org/web/20081211154326/http://www.sectsco.org/fk-03.html. Accessed on 25 August 2020
10. Matveeva and Giustozzi. n. 1
11. Rashid Alimov (former SCO secretary general), 'The Role of Shanghai Cooperation Organization In Counteracting Threats to Peace and Security', *UN CHRONICLE (No 3, 2017)*. p. 35
12. All five Central Asian countries joined OSCE in 1992.
13. All five Central Asian countries joined PfP in 1994 except Tajikistan which joined in 2002.
14. All five Central Asian countries have joined NATO-affiliated Euro-Atlantic Partnership Council as partner countries.
15. Weiqing Song, "Feeling safe, being strong: China's strategy of soft balancing through the Shanghai Cooperation Organization", *International Politics* (2013) 50, 664-685. doi:10. 1057/ip. 2013. 21
16. Abanti Bhattacharya, "Conceptualizing the Silk Road Initiative in China's Periphery Policy", *East Asia* (2016) 33:309–328 DOI 10.1007/s12140-016-9263-9. p. 321
17. Matveeva and Giustozzi. n. 1
18. Weiqing Song. n. 15
19. MK Bhadrakumar, "The New 'NATO of the East' Takes Shape: The SCO and China, Russia And US Manoeuvres", *The Asia-Pacific Journal (1 August 2007), Volume 5/Issue 8*. apjjf.org/-M-K-Bhadrakumar/2503/article.html. Accessed on 8 September 2020

20. Abanti Bhattacharya, "China's 'Observer' Status: Implications for SAARC", *Institute of Peace and Conflict Studies* (21 November 2005). www.ipcs.org/comm_select.php? articleNo= 1891. Accessed on 20 September 2020
21. The Himalayan Times, *SAARC To Grant Observer Status To US, S Korea, EU* (2 August, 2006). http://www. thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=6a6Za3za.9amal&folder=aHaoamW&Name =Home&dtSiteDate=20060802. Accessed on 20 September 2020
22. Xi Jinping, The Government of China website. english.scio.gov.cn/featured/xigovernance/ 2018-6/11/ content_51986400.htm. Accessed on 8 September 2020
23. President of Russia website. en.kremlin.ru/events/president/news/57716. Accessed on 8 September 2020
24. Mirzokhid Rakhimov, 'Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the Future of Regional Integration in Central Asia', in *Asia between Multipolarism and Multipolarity,* eds. Sujan R Chinoy and Jagannath P Panda (Knowledge World: New Delhi, 2020). pp. 135-137 *passim*
25. Alice Wells, quoted in Meena Singh Roy and Rajorshi Roy, " Uzbekistan: The Key Pillar of India's 'Act North' Engagement", *Strategic Analysis*, 2020 Vol. 44, No. 2, 106–124, https://doi.org/10.1080/09700161.2020.1733283
26. Ashok Sajjanhar, *Central Asia Digest (August 2020, Vol 05 Issue 08).* Ananta Centre, New Delhi
27. Congressional Research Service (CRS), *Report no. R45122*
28. SCO website, *Interview of the SCO Secretary General with Press Trust of India*, 22 June 2020. eng.sectsco.org/ news/20200622/659165.html. Accessed on 1 September 2020
29. Ministry of External Affairs website. mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/28518/english+ rendition+ of+ prepared+ text+ of+press+ statement+ by+ prime+minister+ at+sco+ summit… Accessed on 31 August 2020
30. Ministry of External Affairs website. mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dt/29971/ English_translation_of_ Prime_Ministers_Intervention_in_Extended_Plenary_of_18th_SCO_Summit_Ju… Accessed on 31 August 2020
31. Narendra Modi website. narendramodi.in/pm-modi-addresses-the-sco-summit-in-bishkek-545281. Accessed on 31 August 2020
32. Ministry of External Affairs website. mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/31331/Speech+ by+ External+ Affairs+ Minister+at+ the+ Meeting+ Shanghai+Cooperation+ Organization…. Accessed on 31 August 2020
33. Ministry of External Affairs website. Secretary_West_at_ the_inaugural_session_of_the_Webinar_on_ India_and_SCO_relations_hosted_by_ICWA. Accessed on 3 September 2020
34. Dmitry Suslov, "Non-Western Multilateralism: BRICS and SCO in post-COVID World", *Raisina Debates ORF* (29 July 2020). https://www.orfonline.org/expert-speak/nonwestern-multilateralism-brics-sco-post-covid-world/. Accessed on 11 September 2020

ANNEXURE A

HIGH-LEVEL PARTICIPATION IN SCO MEETINGS

Prime Minister's participation in meeting of Heads of State
Minister of Home Affairs' participation in Heads of Emergency Prevention and Relief Agencies meeting
External Affairs Minister's participation in the Council of Foreign Ministers
Minister of State for Law and Justice's participation in Law Ministers' meeting
Commerce and Industry Minister's participation in meeting on external economic and trade
Chief Justice of India's participation in meeting of Chairmen of Supreme Courts
Additional Solicitor General's participation in meeting of prosecutor generals
External Affairs Minister's/Defence Minister's participation in meeting of Heads of Government
Defence Minister's participation in meeting of defence ministers
Minister for Environment, Forest and Climate Change's participation in meeting of environment ministers
Minister of State, Railways' participation in the meeting of railways ministers
Minister of State for Tourism's participation in meeting of tourism ministers
Minister of State for Culture's participation in meeting of culture ministers
Minister of State, Ministry of Human Resource Development's participation in meeting of education ministers
Secretary (West)'s participation in the SCO-Afghanistan Contact Group meeting
Deputy National Security Adviser's participation in the meeting of National Security Advisers
Director General, Narcotics Control Bureau's participation in meeting of heads of agencies combating illegal drug trafficking
Director General, Border Security Force's participation in meeting of heads of border services
Indian participation in anti-terror drill
Indian Armed Forces contingents' participation in Peace Mission Exercise
Joint Urban Earthquake Rescue Exercise
Military Medicine Conference

ANNEXURE B

MoUS SIGNED BY INDIA

Memorandum of Obligations (MoO) as a member
Acceding to 34 SCO agreements, including SCO Charter, Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, and 3 additional SCO agreements subsequently
Prevention of Narcotics Abuse
Environmental Protection
Fight against Threat of Epidemics
Trade Facilitation
Cooperation on MSMEs (medium, small, and macroeconomic sector)
Cooperation on Customs
Cooperation on Tourism
Protocol on the SCO-Afghanistan Contact Group
Memorandum on Technical Cooperation in the Field of Joint Prevention and Control of Trans-
Boundary Diseases
Cooperation in Digitisation and IT Technologies
Cooperation in Development of Inter-regional Cooperation
Cooperation in Mass Media
Cooperation in Physical Education and Sports
Cooperation in World Tourism Organization
Programme of Multilateral Trade-Economic Cooperation

भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य और प्रासंगिकता - एक आकलन

पी स्टोबदान

यूरेशिया केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली में अचानक परिवर्तन के कारण आंतरिक रूप से और दो प्रमुख भू-राजनीतिक खिलाड़ियों-रूस और चीन के बीच होने के नाते बाह्य रूप से महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत सहित सभी प्रमुख शक्तियां सोवियत पश्चात इस रिक्ति में प्रतिस्पर्धी दृष्टि के साथ अपनी क्षेत्रीय स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। एससीओ चीन-रूसी सीमा वार्ताओं की शाखा है, जिसमें आगे चलकर तीन मध्य एशियाई गणराज्य - कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान भी शामिल हो गए। इससे चीन और उसके पड़ोसी पूर्व सोवियत राज्यों के बीच लंबित सीमा के सीमांकन के मुद्दों का पारस्परिक रूप से निपटारा करने के लिए "विश्वास निर्माण" को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1996 में एक ढीले-ढाले क्षेत्रीय गठबंधन "शंघाई पाँच" के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।1 इसने सीमा पर विसैन्यीकरण के लिए "विश्वास निर्माण" भी शुरू किया जिसके बाद 1997 में "सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की पारस्परिक कमी पर समझौते" पर हस्ताक्षर हुआ।2

चीन के शंघाई पाँच के प्रारूप की सफलता ने एससीओ को जन्म दिया और 2001 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने इसका एससीओ के रूप में पुन: नामकरण करने पर सहमति जताई और आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाते हुए मध्य एशिया की सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए इसमें उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया।

निस्संदेह, एससीओ के उद्भव को इसके प्रोफाइल और वैश्विक ध्यानाकर्षण के संदर्भ में यूरेशियन क्षेत्र में उल्लेखनीय घटनाओं में से एक माना जा रहा है। हालांकि, इस समूह को आलोचकों ने सोवियत पश्चात यूरेशिया में रणनीतिक अभिसरण का प्रयास करने के लिए केवल रूसी और चीनी विदेश नीतियों का एक सहक्रियात्मक उपकरण बताया है।

तब से एससीओ यूरेशिया की भूराजनीति में बद्धमूल रहा - जो अपने साझा हितों को विनियमित करने और इस क्षेत्र के देशों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसने मध्य एशियाई राज्यों की अपनी व्यवस्थाओं की रक्षा करने और अमेरिका सहित प्रमुख शक्तियों के साथ भू-राजनीतिक हेजिंग में अपने समीकरणों को संतुलित करने में सहायता की।

एससीओ ने शुरू में अपने आपको मुख्य रूप से बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और सीमा नियंत्रण मुद्दों तक सीमित रखा। इसने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की 'तीन बुरी ताकतों' का मुकाबला करने की शपथ ली।3 हालांकि, 9/11 की घटना और अफगानिस्तान में

आतंकवाद के विरूद्ध परिणामी युद्ध ने एससीओ की कमजोरी को उजागर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप मध्य एशिया में अमेरिकी सेनाओं का प्रवेश हुआ। 12 से अधिक वर्षों तक अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ने कुछ समय के लिए शक्ति संतुलन बदल दिया था जब तक कि अमेरिकी सैनिकों ने 3 जून, 2014 को इस क्षेत्र को छोड़ नहीं दिया।

2002 तक, एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक क्षेत्रीय निकाय के रूप में अधिक मजबूत होना था। इसने संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के लिए आवेदन किया और संभावित सदस्यता के लिए मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान और ईरान को शामिल कर इस समूह का विस्तार करना चाहता था। एससीओ का वृहत्तर उद्देश्य अमेरिकियों को इस क्षेत्र से बाहर रखने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना का निर्माण करने तक व्यापक हो गया है। 4

एससीओ का विकास और सीमा

निश्चित रूप से, शुरू में एससीओ के गठन को पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने के सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय संगठन के रूप में प्रचारित किया गया था। हालांकि, हकीकत में सदस्य देशों के बीच इस संबंध में स्पष्टता की कमी रही है कि एससीओ को कागजी शेर से और आगे बढ़कर कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। एससीओ की कोई भी ठोस प्रगति मायावी रही है क्योंकि सदस्य देशों, विशेष रूप से चीन और रूस ने मुख्य रूप से किसी भी परिवर्तन के बजाय व्यवस्था सुरक्षा का प्रयास करके कुछ मात्रा में क्षेत्रीय स्थिरता प्राप्त करने की परिकल्पना की थी।

इसका एक कारक क्षेत्रीय राज्यों के बीच आंतरिक मतभेद और ठंडे संबंध थे जिससे एससीओ के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जल संसाधनों और भूमि सीमा को लेकर संघर्ष आंतरिक मतभेदों की गंभीरता को रेखांकित करता रहा। उज्बेकिस्तान ने 2016 तक क्षेत्रीय सहयोग का विरोध किया और एससीओ के तत्वावधान में शुरू की जा रही किसी भी मेगा जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध किया। इसलिए एससीओ को सहयोग की किसी सामूहिक भावना के बजाय चीन द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों से ही बचाए रखा गया है।

भले ही एससीओ एक व्यापक क्षेत्रीय निकाय की तरह दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह मध्य एशिया पर चीन-रूसी नियंत्रण बनाए रखने के लिए मोडस विवेंडी रणनीतिक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। "मित्रता और सहयोग पर अच्छी पड़ोसी संधि" पर जून 2001 में हस्ताक्षर होने के बाद से एससीओ ने व्यापार और सीमा विसैन्यीकरण जैसे मुद्दों पर सहयोग करने के लिए रूस-चीन द्विपक्षीय संबंधों को चलाने वाले इंजन के रूप में कार्य किया है, इसकी गतिविधियां प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों के आदान-प्रदान तक ही सीमित थी।[5]

पिछले तीन दशकों तक रूस और चीन ने छोटे सदस्यों के नेताओं को वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर अपनी नीतियों का समर्थन करने के लिए मजबूर करते हुए इस समूह पर प्रभुत्व कायम रखा। चीन विशेष रूप से उइगर अलगाववादियों का प्रत्यर्पण करने के लिए मध्य एशियाई सरकारों से उनकी सहमति के संदर्भ में बड़ी नीतिगत रियायत हासिल करना चाहता था जिन्होने पड़ोसी कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में शरण लिया था।

वहीं दूसरी ओर मध्य एशियाई राज्यों ने धार्मिक और राजनीतिक समूहों के दबाव को दूर करने के लिए अपने घरेलू कारणों से एससीओ का इस्तेमाल किया।6 उज्बेक राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव और

कजाख राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव सहित मध्य एशियाई नेताओं ने पूरे दिल से एससीओ के गठन का स्वागत किया।7 बदले में, दोनों बड़ी शक्तियों ने बार-बार आंतरिक विपक्षी समूहों को कुचलने वाली क्षेत्रीय निरंकुश व्यवस्थाओं की रक्षा की।

एससीओ में वृद्धि करने की आंतरिक सीमा भी थी। इसके पास एक या दो राज्यों के प्रभुत्व वाले अंग के बजाय क्षेत्र के सामूहिक हितों के लिए प्रयास करने के लिए यूरोपीय संघ या आसियान जैसे स्वायत्त विश्वसनीय संगठन के रूप में उभरने के लिए आवश्यक विकासवादी प्रक्रियाओं-राजनीतिक इच्छाशक्ति, आर्थिक मजबूती और संगठनात्मक ढांचे का अभाव था।

एससीओ में भारत का दाँव

एससीओ अनिवार्य रूप से यूरेशियाई भूराजनीति के लिए एक नाजुक संतुलन परिलक्षित करता है और भारत ने कभी उक्त गतिशीलता को प्रकट नहीं किया। हालांकि यह सत्य है कि मध्य एशियाई लोगों ने हमेशा इस क्षेत्र में एक प्रतिकारी कारक होने की भारत की क्षमता को अनुभव किया है। इस अभिव्यक्ति ने सरकारों के भीतर और बाहर घोषणा पाई। इसके साथ ही, मध्य एशियाई राज्यों ने महसूस किया कि भारत के पास इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए सक्रिय ढांचे का अभाव है।

भारत के दृष्टिकोण से, एससीओ को एक आदर्श राजनीतिक और आर्थिक तंत्र के रूप में देखा जाता है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में और उसके आसपास अस्थिर स्थिति को नियंत्रण में रखने और संपूर्ण एशिया में बढ़ते चीनी प्रभाव के विरूद्ध इसकी सुरक्षा गणना में फिट बैठता है। यह क्षेत्र में पाकिस्तान की तुलना में भारत के सामरिक हितों को बट्टा लगाने के लंबे समय से रखे गए पश्चिमी दृष्टिकोण से आवश्यक हो गया था।

हालांकि, मध्य एशियाई देशों ने रूसी प्रभुत्व वाले क्षेत्रीय सेटिंग के भीतर रहने का फैसला किया, उन्होंने क्षेत्रीय एकीकरण के लिए भी पहल की, हालांकि बिना ज्यादा सफलता के। अपने समीकरणों को संतुलित करने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक और आर्थिक संपर्कों को व्यापक बनाने के लिए अमेरिका, भारत और जापान सहित प्रमुख बाहरी शक्तियों के साथ भू-राजनीतिक हेजिंग भी की। मोटे तौर पर, उन्होंने प्रमुख खिलाड़ियों के हितों को संतुलित करने के तरीके के रूप में मल्टी-वेक्टर विदेश नीति का पालन किया। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उनके द्वारा भारत को इस क्षेत्र में एक संभावित प्रतिकारी कारक के रूप में देखा जाता है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत ने महसूस किया कि वह रणनीतिक यूरेशियाई क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता, जहाँ केवल एससीओ एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक ध्रुव के रूप में उभरा है। इसलिए, तर्क की मांग थी कि इसके बाहर होने से इसमें होना बेहतर है।

एससीओ कूटनीतिक रूप से भी एक प्रासंगिक निकाय बन गया। अच्छे पड़ोसी और क्षेत्रीय समस्याओं के संयुक्त समाधानों की "शंघाई भावना" के रूप में बड़े करीने से पैक किया गया एससीओ के चार्टर का वर्णित उद्देश्य इसमें होने के लिए भारत के लिए आकर्षक सिद्ध हुआ।

बहु-ध्रुवीयता के लक्ष्य को बढ़ावा देने में रुचि के अलावा, भारत के पास एससीओ का हिस्सा बनने के लिए दांव और प्रत्यक्ष संभावित लाभ था। इनमें यूरेशियाई सदस्यों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने के तरीके तलाशने और अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं, विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठन का लाभ उठाने उद्देश्य शामिल था। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, नई दिल्ली ने संगठन में औपचारिक प्रवेश का उत्सुकता से अनुगमन किया और 2005 में इस समूह का पर्यवेक्षक बन गया, बावजूद इसके कि घर में आलोचक कम राजनीतिक आवाज के साथ एक कनिष्ठ सदस्य के रूप में एक चीनी नेतृत्व वाले निकाय में शामिल होने की बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे थे।

एससीओ में प्रवेश को भारत के लिए एक सदी के व्यवधान के बाद यूरेशिया के साथ फिर से जुड़ने के नए अवसर के रूप में देखा गया। सोवियत पश्चात क्षेत्रीय एकीकरण में शामिल होना पारंपरिक भारत-रूसी विरासतों की गति जारी रखने के लिए भी जरूरी हो गया था, अलबत्ता एक नए बहुपक्षीय

प्रारूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उफा शिखर सम्मेलन में कहा कि एससीओ की सदस्यता "सदस्य देशों के साथ भारत के संबंधों का स्वाभाविक विस्तार होगी।" 8

भारत की सुरक्षा अनिवार्यताएं इस क्षेत्र के भीतर बड़ी-बड़ी हैं जैसे कि आतंकवाद का प्रसार, अफगान विवाद और मध्य एशिया में आईएसआईएस की बढ़ती पैठ। एससीओ के संभवतः भारत विरोधी आवाजें उठाने वाली विरोधी ताकतों का मंच बनने के प्रति सचेत होना चाहिए। विचार एससीओ के आरएटीएस का दोहन करके लाभ उठाने का था जो आतंकवादियों की आवाजाही और मादक पदार्थों

की तस्करी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और खुफिया जानकारी साझा करता है। इसी तरह एससीओ के आतंकरोधी अभ्यासों और सालाना किए जाने वाले सैन्य अभ्यास में भागीदारी से भारतीय सशस्त्र बलों को अन्य सेनाओं की परिचालन रणनीति समझने में फायदा मिल सकता है जिससे क्षेत्रीय स्तर पर भी अधिक विश्वास पैदा हो सकता है।

इससे भी गंभीर बात यह है कि मंच में उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी कि भारत विरोधी ताकतें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत विरोधी रूख का नगाड़ा पीटने के लिए इस निकाय में हेरफेर न कर पाएं जिसमें मुस्लिम आबादी वाले राज्य हैं। मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण, साइबर सुरक्षा खतरों, सार्वजनिक सूचना, जनसंचार माध्यम, शैक्षिक, पर्यावरणीय, आपदा प्रबंधन और यूरेशिया के पानी से संबंधित मुद्दों जैसी जानकारी प्राप्त करने में भी प्रत्यक्ष दाँव देखा गया, जिनके बारे में भारत न के बराबर जानता था।

चूंकि अफगानिस्तान में स्थिति अनिश्चित बनी हुई थी, इसलिए एससीओ, जितना यह चाहता था, ने दक्षिण एशियाई देशों की अनदेखी करना मुश्किल पाया। अमेरिका-ईरान विरोधी संबंधों के विपरीत अमेरिका के साथ भारत-अफगान अनुकूल संबंध एससीओ के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गए।

पहला, भारत के लिए सदस्यता वापसी के बाद अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी थी। हालांकि एससीओ और सीएसटीओ दोनों द्वारा ही "रक्षात्मक" भूमिका से अधिक निभाने की संभावना नहीं थी, लेकिन भारत अफगान शांति के लिए सकारात्मक राजनीतिक माहौल पैदा करने के संदर्भ में मूल्य वर्धन प्रदान कर सकता था। अफगानिस्तान में शक्ति रिक्तता की संभावना नहीं थी; हालांकि, भारत विरोधी नकारात्मक ताकतें एससीओ तंत्र के माध्यम से अपने हित को आगे बढ़ा सकती थीं।

दूसरा, रूस और पाकिस्तान तेजी से पुल बना रहे हैं, जिसकी रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है,जो मध्य एशिया में भारत के हितों को प्रभावित करेगा। पाकिस्तान यूरेशियाई क्षेत्र में और अधिक राजनीतिक स्वीकार्यता हासिल कर सकता है और वह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने समर्थन को ढंकने के लिए इस मंच का स्मोकस्क्रीन के रूप में उपयोग कर सकता है। आगे अफगानिस्तान में जो भी सत्ता में आएगा, उस पर अमेरिका का नियंत्रण होने की संभावना है। भारत को यह देखना चाहिए कि क्या काबुल एससीओ को लेकर अमेरिकी संदेहों को दूर करने में सक्षम होगा और उसे सदस्यता लेने की अनुमति देगा। अफगानिस्तान मंगोलिया के साथ एससीओ के साथ अपना तालमेल बैठाने को लेकर अब तक सतर्क रहा है।

तीसरा, मुख्य रूप से चीन की लगातार रूचि और इन राज्यों के साथ जुड़ाव के कारण एक हद तक एससीओ मध्य एशिया में उग्रवाद और आतंकवाद का प्रसार नियंत्रित करने में सफल रहा है। यह क्षेत्र सांप्रदायिक संघर्ष का अगला अड्डा बन सकता है। यह अगला उभरता हुआ मुस्लिम क्षेत्र है। मौजूदा एससीओ राज्यों में बड़ी मुस्लिम आबादी है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान से संबद्धता के साथ सुन्नी/सलाफी प्रकार के भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चेचन्या, फरगना और शिनजियांग के भविष्य में अस्थिरता का चाप बनने की संभावना है।

एससीओ के साझा सुरक्षा खतरों की संकल्पना "तीन बुराइयों" के विरूद्ध लड़ाई के रूप में की गई है। आरएटीएस का अनुच्छेद 6 प्रासंगिक एससीओ निकायों के प्रस्तावों और सिफारिशों पर और तीन बुराइयों से निपटने के पक्षकारों अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए प्रमुख उद्देश्यों और कार्यों को स्पष्ट करता है। आरएटीएस फरगना घाटी में और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमू दरिया के पार फैलते कट्टरपंथी राजनीतिक इस्लाम के रुझानों के प्रेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत को इस क्षेत्र में उभरते रुझानों को समझने की जरूरत है और यह केवल एससीओ में होकर ही हासिल किया जा सकता है।

भारत आरएटीएस के साथ संबंधों से लाभ प्राप्त कर सकता है जैसे कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आदि पर जानकारी। ऐसा लगता है कि आरएटीएस सम्मेलन की तैयारी, शिखर सम्मेलन की बैठकों, वीआईपी दौरों, सार्वजनिक बैठकों, खेल कार्यक्रमों के दौरान जानकारी साझा करने में अपने सदस्यों की सहायता करता है। आरएटीएस के चार्टर में खुफिया जानकारी साझा करना और उग्रवादी समूहों, कर्ताओं, व्यक्तियों की सूची संकलित करना शामिल है जो इस क्षेत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं।

इसके मुख्य कार्यों और कर्तव्यों में शामिल हैं:

- सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सक्षम संस्थानों के साथ काम कर रहे संबंधों को बनाए रखना;
- खुफिया जानकारी साझा करना;
- संबंधित सदस्य देशों के अनुरोध पर आतंकवाद विरोधी अभ्यास की तैयारी, खोज अभियानों की तैयारी और संचालन में सहायता करें;
- अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों का संयुक्त मसौदा तैयार करना;
- जानकारी का एकत्रन और विश्लेषण, उग्रवादी समूहों, अभिनेताओं, आरएटीएस डेटा बैंक के लिए व्यक्तियों की सूची संकलित करना;
- संयुक्त रूप से वैश्विक चुनौतियों और खतरों का जवाब;
- सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन और क्षेत्र में अनुभव साझा करना।

ऐसा लगता है कि आरएटीएस ने आतंकी नेटवर्कों, विचारधारा और दुष्प्रचार के प्रसार, सीमा पार संगठित अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण और धन शोधन के बारे में जानकारी जुटाने के मामले में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। इसमें सीमा पार अपराधों को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सहयोग तंत्र है।

यह नियमित रूप से धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने और क्षेत्र में काम कर रही अन्य एजेंसियों पर यूरेशियन समूह की बैठकों में भाग लेता है। साइबर सुरक्षा आरएटीएस में एक प्रमुख संस्थागत तंत्र है जो सदस्य देशों के सक्षम अधिकारियों के साथ बातचीत करता है।

यह एससीओ राज्यों के लिए एक संरक्षित सूचना और दूरसंचार सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक आयोजित करता है। यह आतंकी समूहों द्वारा इंटरनेट के उपयोग का मुकाबला करने पर "श्यामेन-2015" संयुक्त कमान-पोस्ट अभ्यास जैसे ऑनलाइन आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित करता है।.

आरएटीएस प्रतीत होता है ठोस परिणाम प्राप्त किया है: "500 आतंकवादी अपराधों पर अंकुश लगाया, 440 से अधिक प्रशिक्षण ठिकानों का सफाया; अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के 1050 सदस्यों को पकड़ा, 654 तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों, 5000 से अधिक आग्नेयास्त्रों, 46 टन विस्फोटकों और 500 हजारों से अधिक गोला बारूद जब्त किया। 9

आरएटीएस की वेबसाइट से पता चलता है कि एससीओ के सदस्य देशों ने अकेले 2015 में 167 आतंकवादी और चरमपंथी अपराधों को टाल दिया है। 200 से अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक आरोप लगाए गए थे। 150 आतंकवादियों को समाप्त किया गया,

लगभग एक हजार उकसाने वाले पकड़े गए, दो सौ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और 1500 हथियार थे जब्त।10 अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आरएटीएस ने सीआईएस काउंटर-टेररिस्ट सेंटर और सीएसटीओ के साथ प्रोटोकॉल और समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आम यूरेशियन स्पेस में बड़े पैमाने पर सुरक्षा सहयोग व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

नई आतंक विरोधी मसौदा रणनीति

एससीओ ने 31 मार्च, 2017 को आतंकवाद, आतंकवादी कृत्य और आतंकवादी संगठनों पर एकल समेकित कानूनी ढांचे पर एक मसौदा सम्मेलन अपनाया। इससे पहले के मसौदे में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने पर शंघाई कन्वेंशन (2001) और आतंकवाद के विरूद्ध कन्वेंशन (2009) शामिल थे जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में आतंक और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना था। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की अस्ताना घोषणा में कहा गया है कि "सदस्य देश आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उपयोग से संबंधित व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों का प्रतिकार करने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए सार्वजनिक आह्वान या आतंकवाद के कृत्यों के औचित्य और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सहयोग जारी रखेंगे।

वार्षिक "शांति मिशन"

एससीओ सैन्य सहयोग में अपने वार्षिक "शांति मिशन" या "आतंकवाद विरोधी" अभ्यासों का नियमित संचालन शामिल है। अभ्यास आतंक विरोधी कमान समन्वय अभियानों और लड़ाकू तत्परता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन संयुक्त अभ्यासों की योजना और समन्वय एससीओ की वार्षिक रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठकों के ढांचे के भीतर होता है। जून 2017 रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन और संरक्षण के लिए आशय के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसने 2018-2019 के लिए एससीओ रक्षा मंत्रालयों की सहयोग योजना को भी मंजूरी दी।

मैत्री और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एससीओ रक्षा मंत्रालयों का पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया गया है जो संगठन के रक्षा मंत्रालयों के बीच बेहतर सहयोग को मजबूत करने में योगदान देते हैं। 2014 के बाद से, एससीओ सदस्य देशों से भाग लेने वाले सैन्य बैंड के साथ सैन्य संगीत समारोह "शांति का तुरही" आयोजित कर रहा है।

रूसी इन अभ्यासों के लिए आम ऑपरेटिंग भाषा रही है, लेकिन हाल के वर्षों में चीनी भाषा को अंतरसंचालनीयता में सुधार के लिए जोड़ा गया है। यह देखने की जरूरत है कि भारत और

पाकिस्तान की एंट्री के साथ इसमें अंग्रेजी जोड़ी जाएगी या नहीं। एससीओ की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अंग्रेजी शुरू करने के विरूद्ध बहुत प्रतिरोध किया गया है।

अन्य लाभ

जाहिर है, यह धारणा थी कि दीर्घावधि में एससीओ भारत को अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त अक्षांश प्रदान करने में सहायता करेगा-पाइपलाइन मार्गों पर अपना रास्ता पाने के लिए एक आंख के साथ तेल क्षेत्रों में निवेश करना। एससीओ तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए सुरंग के अंत में प्रकाश देखने का रास्ता भी बदल सकता है, जिसकी व्यवहार्यता को अब तक कई कारणों से खतरा था।

बड़े यूरेशियन एकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के अन्य कारण भी थे। उदाहरण के लिए, भारत पारस्परिक रूप से निर्माण करने के लिए उत्सुक था क्षेत्र के साथ अपनी तकनीकी-आर्थिक विशेषज्ञता,

बाजार और वित्तीय प्रतिबद्धता साझा करते हुए लाभकारी साझेदारियां। मध्य एशिया के देशों के लिए बहु-सांस्कृतिक सेटिंग्स से निपटने में भारत का अनुभव एक आकर्षण है क्योंकि वे अफगानिस्तान में भारतीय रचनात्मक प्रयासों की भी सराहना करते रहते हैं।

कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भारत सीपीईसी द्वारा पेश की गई चुनौती के प्रति सजग था। बीआरआई/सीपीईसी के तहत परिकल्पित परियोजनाओं का एक सेट भारत के तत्काल आसपास के क्षेत्र में बदलने के लिए बाध्य था जिसका भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

.

इन घटनाक्रमों के विरूद्ध भारत ने 2016 में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए निवेश करने का फैसला किया और अफगानिस्तान और मध्य एशियाई राज्यों से जुड़ने के लिए उत्तर में चाबहार से जहेदान तक 610 किलोमीटर लंबी रेलवे बनाने की योजना बनाई। दरअसल, चाबहार की घोषणा और 2016 में अफगानिस्तान में मैत्री (सलमा) बांध के उद्घाटन ने भी क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत दिया था। मार्च 2016 में भारत ने अशगाबात समझौते को स्वीकार करने का अनुरोध किया था। अशगाबात समझौते में भारत का प्रवेश विशेष रूप से दिसंबर 2017 में चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहश्ती टर्मिनल के पहले चरण के उद्घाटन के कुछ ही समय बाद हुआ था जिसे भारत द्वारा वित्तपोषित (85 मिलियन अमेरिकी डॉलर) द्वारा वित्तपोषित किया गया था। भारत के लिए चाबहार के परिचालन और व्यावहारिक दायरे दोनों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा भूमि मार्ग बनने की एक बड़ी संभावना खुल गई है।

यूरेशिया में अपनी बीआरआई परियोजनाओं पर चीन के आक्रामक और व्यापक रुख ने शायद भारत को आईएनएसटीसी को आगे बढ़ाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान, रूस और काकेशस के अन्य राज्यों में शामिल होने के तरीके खोजने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी।

अशगाबात समझौते को स्वीकार करने के अलावा, भारत ने (19 जून, 2017 को) को अंतर्राष्ट्रीय माल के कवर कवर ऑफ टीआईआर कार्नेट (टीआईआर कन्वेंशन, 1975) पर सीमा शुल्क कन्वेंशन में भी स्वीकार किया, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय कैरिज ऑफ गुड्स के लिए किया जाता है। टीआईआर कार्नेट ट्रांजिट कार्गो की आवाजाही के लिए प्रमुख सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा शुल्क पारगमन दस्तावेज़ है कि ट्रक चालक और मूल से गंतव्य के लिए सीमा शुल्क बिंदुओं भर में कार्गो के साथ isan। इन पहलों का उद्देश्य यूरेशियन क्षेत्र के भीतर भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और आईएनएसटीसी सहित उस क्षेत्र के अन्य परिवहन गलियारों के साथ इसे सिंक्रोनाइज करना था।

शुरू में यह प्रतीत होता था कि भारत एससीओ प्रक्रिया के तहत अवसरों का पूरी तरह से दोहन करना चाहता था, इसलिए 2017 में बिना किसी अस्पष्टता के नए दिमाग से संगठन में शामिल हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए, नई दिल्ली इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए भू-राजनीतिक गणनाओं के प्रति सजग था।

भारत की सदस्यता

भारत को 2014 में पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करने से पहले दस साल तक इंतजार करना पड़ा जब एससीओ ने नए खिलाड़ियों के लिए कानूनी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। जुलाई 2015 में उफा शिखर सम्मेलन में रूस द्वारा पीएम मोदी को आमंत्रित करने के बाद औपचारिक प्रवेश की संभावना प्रशंसनीय हो गई। दरअसल, उम्मीद थी कि यह सदस्यता उफा समिट में आएगी। हालांकि, यह पता चला कि मंच केवल एक लिया

भारत (और पाकिस्तान) को स्वीकार करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करने का सैद्धांतिक निर्णय। इसके बाद, औपचारिक प्रवेश के लिए और दो साल लग गए-मानदंड, नियम, प्रक्रियाओं और एक समय रेखा निर्धारित करने में विफलता का हवाला देते हुए, जिसने क्षेत्रीय समूह में भारत के प्रवेश में देरी की।

प्रवेश दस्तावेजों को 2016 में पूरा कर लिया गया था लेकिन दोनों आवेदकों, भारत और पाकिस्तान को ' प्रतिबद्धताओं पर ज्ञापन ' पर हस्ताक्षर के माध्यम से एससीओ प्रक्रियाओं के अनुसार लगभग 30 अनिवार्य मसौदा दस्तावेजों को अपनाना आवश्यक था। इनमें से, प्रमुख दस्तावेज ' अच्छे पड़ोस ' से संबंधित है जिसे पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले नए आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे। दूसरे शब्दों में, भारत को एससीओ की उम्मीदों का पालन करना था-एक पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में प्रवेश करने से पहले पड़ोसी देशों के बीच ' शांति संधि ' के बराबर।

जाहिर है, कागजी कार्रवाई चीन के लिए एससीओ को अपने अनन्य डोमेन के रूप में रखने का महज एक बहाना प्रतीत होती है, जिसमें भारत को शामिल करना प्राथमिकता नहीं थी-या यहां तक कि एक आवश्यकता भी। हालांकि भारत के प्रवेश में देरी का मतलब पाकिस्तान और ईरान के लिए भी ऐसा ही करना था, लेकिन बीजिंग ने इस्लामाबाद और तेहरान से निपटने के लिए अन्य खिड़कियां खोली थीं।

एससीओ के अन्य लोगों को दक्षिण एशियाई संघर्षों में फंस जाने के बारे में गलतफहमी थी-सार्क की विफलता अक्सर एक बहाना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उज्बेक के पूर्व राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव ने उफा शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान को समूह में शामिल करने से एससीओ 11 का स्वरूप बदल जाएगा।

विस्तार का दूसरा कारण एससीओ की गतिविधियों में उपलब्धियों का अभाव था। एक दशक से अधिक के लिए, एससीओ की प्रगति अपनी उच्च दृश्यता के बावजूद अपनी प्रभावकारिता और प्रोफ़ाइल दोनों में धब्बेदार रही। इसकी उपलब्धियों को चीन की द्विपक्षीय पहलों के सूचकांक के रूप में अधिक देखा गया और इसकी बाहरी छवि चीनी वित्तपोषण द्वारा बचाए रखे गए ' निरंकुश क्लब ' की थी। हालांकि, सितंबर 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा ' वन बेल्ट, वन रोड ' (OBOR) या बीआरआई का अनावरण करने के बाद हालात बदल गए-आर्थिक और बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के माध्यम से यूरेशिया को एकीकृत करने की योजना। 12व एससीओ ने उस साल 2025 तक अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर चर्चा करने के लिए बातचीत का 6 + 2 प्रारूप भी बनाया और तब से इस मुद्दे को अपनी शिखर बैठकों में बड़ा रूप दिया।.

इसलिए, क्या वास्तव में विस्तार के मुद्दे को प्रेरित कनेक्टिविटी और बाजार एकीकरण को बढ़ाने के लिए चीन की धक्का था। नतीजतन, भारत ने अचानक राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पथरी में उच्च चित्रित किया, जिन्होंने कहा कि भारत-चीन संबंधों में सुधार उनका "ऐतिहासिक मिशन" होगा। सामान्य स्थिति का माहौल और सीमा पर शांति की भावना भी प्रबल हुई।

एससीओ की धीमी प्रगति का कारण रूस और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा की गहरी अंडरकरंट को भी माना गया। लेकिन रूस के ईएईयू और चीन के बीआरआई के बीच पूर्ण तालमेल स्थापित करने के लिए पुतिन और शी के बीच हुई सहमति के बाद २०१५ में संदर्भ बदल गया।

बेशक, यूक्रेन में घटनाओं मध्य एशिया में एक लहर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के आगामी नतीजों और तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण यूरेशिया को आउटलेट की तलाश करनी पड़ी थी। क्षेत्रीय राज्य रूस के बारे में चिंतित थे नए साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति और उनकी संप्रभुता के नुकसान से डरते हैं। इसके अलावा, बढ़ती चीन-रूसी निकटता ने कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान जैसे क्षेत्रीय राज्यों को अपने तत्काल पड़ोस से परे विविधीकरण की तलाश करने के लिए चिंता की एक डिग्री पैदा की थी। दरअसल, इन घटनाक्रमों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों में भारत, ईरान और अन्य की भागीदारी पर विचार किए बिना एससीओ का विकास होगा।

इसके अलावा, सुरक्षा चिंताओं विशेष रूप से 2014 के बाद से अफगानिस्तान से अमेरिका के ड्राडाउन की संभावना, आईएसआईएस के बढ़ते पैरों के निशान और चीन के शिनजियांग प्रांत में आतंकवादी घटनाओं की बाढ़ एससीओ के विस्तार के लिए बाध्यकारी कारक बन गए थे।

भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि

एससीओ का विस्तार यूरेशिया से 'इंडो-पैसिफिक' तक बड़ी शक्ति प्रतिद्वंद्विता के तीव्र वैश्विक पुनर्संतुलन खेल की पृष्ठभूमि के विरूद्ध आया था। जाहिर है, एससीओ मुख्य रूप से चीन-रूसी आमादा पर वेल्डेड है-दोनों का उद्देश्य अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के लिए एक वजन और 2013 के बाद से कनेक्टिविटी के लिए बीजिंग की नई योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जबकि, रूस ने स्पष्ट रूप से समूह की उपयोगिता को वैचारिक दृष्टि से पश्चिम के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा। हालांकि, चीन के लिए यह अपने भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक हितों के विस्तार के लिए एक वाहन था। उदाहरण के लिए, ताशकंद मंत्रिस्तरीय बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एससीओ को वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग का प्रतिमान और आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए एक मॉडल बताया। 13

भारत ऐसे समय में यूरेशियन समूह में शामिल होने की इच्छा रखता था जब नई दिल्ली ने भारत-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए निर्णायक के अमेरिका के रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ खुद को अधिक निश्चित रूप से गठबंधन किया था-अब चीन नियंत्रण रणनीति के लिए एक व्यजकता नहीं है। 14वहवर, रूस और अन्य फिर भी भारत में रस्सी बनाने की कामना करते थे ताकि समूहीकरण को ताजे जीवन शक्ति, अधिक आवाज और प्रतिष्ठा प्रदान की जा सके। , जो अब तक चीन केंद्रित रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में शामिल होने

एससीओ का मतलब समूह को अधिक वैधता देना था, अब तक विशेष रूप से पूर्व कम्युनिस्ट राज्यों का प्रभुत्व है। भारत के भौगोलिक आकार, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक अर्थव्यवस्था के साथ इसकी 1.2 बिलियन आबादी ने एससीओ को दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक बना दिया। लेकिन, यह रूस ही था जिसने शुरू में पूर्ण सदस्यता के लिए भारत के मामले को धक्का दिया। दूसरी ओर चीन पाकिस्तान की एंट्री के लिए धक्का-मुक्की करना चाहता था। केवल मंगोलिया का एक सदस्य के रूप में स्वागत किया गया था लेकिन यूरेशियन समूह में शामिल होने में संकोच था। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने ईरान के प्रवेश में बाधा डाली। लेकिन बीजिंग अंततः भारत और पाकिस्तान को SCO.15 में लाने पर अधिक केंद्रित हो गया, यहां तक कि भारत-पाक संबंधों को भी अब कोई समस्या नहीं लग रही थी बल्कि एससीओ के प्रोफाइल और मूल्य को बढ़ावा देने का अवसर था। चीनी नेतृत्व ने हालांकि एससीओ में भारत के राज्यारोहण का स्वागत किया जब पीएम मोदी ने 2015 में चीन का दौरा किया था। यकीन के लिए, चीन एससीओ के sraison d' etre और उसके चार्टर्स के लिए भारत की पूरी प्रतिबद्धता के बारे में अनिश्चित हो सकता है। बीजिंग इस बात को लेकर सहमत था कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रूस, एक गुटनिरपेक्ष देश या अमेरिका के सहयोगी के साथ मित्रता कर रहा था।

हालांकि विस्तार के मुद्दे पर बहस हुई है, लेकिन इसमें और सकारात्मक विचार सामने आए एससीओ पर्यवेक्षक राज्यों को शामिल करने के पक्ष में है जो एससीओ को भी अधिक आवाज प्रदान कर सकता है। राजनीतिक विचारों ने बेलारूस जैसे अन्य गैर-यूरेशियन राज्यों को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल करने के महत्व को भी रेखांकित किया। इसके अलावा आर्मेनिया, अजरबेजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका को संवाद सहयोगी के रूप में। इस सबने 2016-2017 तक एससीओ की संगठनात्मक बनावट में काफी बदलाव किया है।

भारत के लिए, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समूह में पूर्ण विश्वास करने और रचनात्मक भावना से सदस्यता लेने के बाद स्पष्टता की भावना उभरी। 16PM ने एससीओ के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के बारे में बात की क्योंकि उन्होंने एससीओ में भारत की आकांक्षाओं को भी ठीक-ठाक किया, विशेष रूप से अर्थशास्त्र, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग में लाभ के लिए, निश्चित रूप से कुछ लाल रेखाओं पर जोर दिया-"क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, आतंक के विरूद्ध एकजुट हों"।

इसलिए एससीओ निश्चित रूप से भारत के लिए एक नई सीमा बन सकता है। जहां तक भारत के लिए संभावित लाभों की बात है, एससीओ के व्यावहारिक निहितार्थ निकट अवधि में नाटकीय होने की संभावना नहीं है लेकिन लंबे समय में समूह क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक ऐसा माहौल बना सकता है जिससे भारत को लाभ होगा।

एससीओ और भारत की विदेश नीति संतुलन

एससीओ में भारत की सदस्यता के बाद से भारत-अमेरिका संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। चीन के मन में अब तक मौजूद किसी भी अस्पष्टता को शायद जून 2017 में पीएम मोदी की वाशिंगटन यात्रा के बाद हटा दिया गया है। सैन्य और तकनीकी सहयोग समझौतों की सीमा को देखते हुए द्विपक्षीय संबंध अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ने के लिए बाध्य थे।

नई दिल्ली के लिए, अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों का मतलब दूसरों को यह संकेत देना नहीं है कि वाशिंगटन के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों को रूस और चीन के साथ संबंधों को बढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए, जिसके लिए भारत के पास पहले से ही ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), रूस-भारत-चीन (आरआईसी) और एससीओ जैसे संबंधों के लिए कई रास्ते हैं। भारत चीन के नेतृत्व वाले एआईआईबी में शामिल हो गया। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंध अजेय रूप से बढ़ रहे थे। इसी तरह भारत और रूस रणनीतिक साझेदारी समझौतों को मजबूत करने के लिए

प्रतिबद्ध हैं और रूस के नेतृत्व वाले ईएईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी सहमत हुए।

इसके साथ ही, नई दिल्ली के पास सीमा पर चीन के लगातार उकसावे के विरूद्ध शिकायत को आश्रय देने और अपने पड़ोसियों को लुभाने के लिए भारत को घेरने के लिए गंभीर रणनीतिक कदम उठाने के अपने अपने कारण थे। दरअसल, चीन के उकसावे ने भारत को अपनी क्षमताओं और जवाबी चालों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त कारण दिए, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को वियतनाम को बेचने का फैसला भी शामिल है।

यकीन मानिए, भारत का अपना उद्देश्य अमेरिका और चीन के हितों को एक दूसरे के विरूद्ध नहीं निभाना था बल्कि दोनों शक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाने के साथ-साथ रूस के साथ-साथ वैश्विक रणनीतिक क्षेत्र में बैलेंसर भूमिका निभाना था। तब उम्मीद की जा रही थी कि एक बार ईरान एससीओ में शामिल हो जाए तो शायद भारत संतुलन की भूमिका निभाने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। हालांकि, भारत-अमेरिका के बीच एशियाई क्षेत्र में साझा मूल्यों और हितों को बढ़ावा देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़ना था। अमेरिका के आभासी '

भारत और शंघाई सहयोग संगठन: तीन निबंध

सहयोगी ' के लिए धक्का निर्णय भारत के लिए स्थिति और भारत की इच्छा को संरेखित करने की लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) ने एससीओ में भारत के जुड़ाव को लेकर कई संदेह पैदा किए थे। जाहिर है, यह पश्चिमी प्रभुत्व के लिए एक काउंटर शिष्टता बनने की एससीओ की आकांक्षा का खंडन करने के लिए बाध्य किया गया था। जाहिर है, एससीओ के भू-राजनीतिक अंतरिक्ष के माध्यम से नेविगेट करने का भारत का कार्य अब से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

एससीओ की उपलब्धियां और भारत

अब तक, एससीओ की उपलब्धियां तुरही को उड़ाने के अलावा कम से कम हुई हैं, यह कितनी आबादी और क्षेत्र रखती है। इसके घोषणात्मक राजनीतिक पहलुओं का पश्चिमी शक्तियों द्वारा बार-बार उपहास और आलोचना की गई है।

जहां तक भारत की बात है, इसमें अब तक शामिल होना काफी हद तक प्रतीकात्मक महत्व बना हुआ है। भारत के लिए इसका क्या अर्थ है- चाहे अवसर हो या जोखिम हो या जाल हो, इस बारे में स्पष्टता की कमी है। अब तक जनमत को मिलाया गया है।

वर्षों से यह प्रतीत होता है कि भारत को यूरेशियन भूराजनीति और इसमें एससीओ की भूमिका की बेहतर समझ की जरूरत थी। नई दिल्ली ने एससीओ में चीन के बड़े हितों पर विचार किए बिना आतंकवाद का मुकाबला करने के संकीर्ण नजरिए से शायद एससीओ को देखा जो नए राज्यों के साथ सीमाएं तय करने के एजेंडे से परे बढ़ा है ताकि उन्हें अपने रणनीतिक दायरे में लाया जा सके।

अब तक के रुझानों से पता चलता है कि चीन ने मध्य एशिया में अपनी पाकिस्तान नीति को दोहराने की नीतिगत योजना अपनाई है। एक सावधान विश्लेषण इंगित करता है कि चीन की अवधारणा दाढ़ी एक कई लेकिन विचारों की परस्पर संबंधित लाइनों के साथ चले गए: एक) अपनी क्षेत्रीय समस्याओं और सुरक्षित सीमाओं को हल; ख) शिनजियांग के लिए किसी भी संभावित खतरे को रोकना और अपने उईघुर प्रवासियों को जांच में रखना; ग) यूरेशियन बाजारों के लिए एक निर्णायक लिंक प्राप्त करें।

.

हाल के वर्षों में, बीजिंग ने यूरेशिया में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने, मध्य एशिया में रूसी शक्ति निर्वात को भरने, चीन की पश्चिमी सीमा के लिए किसी भी इस्लामी खतरे को रोकने और भारत जैसी अन्य शक्तियों का मुकाबला करने के लिए इसे एकात्मक साधन के रूप में इस्तेमाल किया।

संराजकों को यह भी आश्चर्य होता है कि क्या एससीओ का भारत के लिए किसी विशिष्ट कार्य और लाभ के मामले में कोई परिणाम है। उनका सुझाव है कि चीन के नेतृत्व वाले क्लब में शामिल होना एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि भारत पूर्व कम्युनिस्ट राज्यों के एक क्लब में एक अजीब बना रहेगा।

आतंकवाद पर विरोधाभास

एससीओ को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से लेकर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने तक कई परस्पर विरोधी हितों का सामना करना पड़ सकता है और भारत की स्थिति कभी-कभार अन्य सदस्यों के साथ मुश्किलों में पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, चीन अपने दावे से एससीओ के माध्यम से "तीन बुराइयों" -आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक चरमपंथ के विरूद्ध लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें दूसरों की सुरक्षा में तोड़फोड़ करने के औजार के रूप में आंतरिक संघर्ष का इस्तेमाल नहीं करने का वादा किया गया है और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड लागू करने का विरोध किया गया है। हालांकि, व्यवहार में आतंकवाद पर बीजिंग की दोहरी बात काफी स्पष्ट रही है।

इसने एससीओ का इस्तेमाल केवल आतंक के उन मामलों से लड़ने के लिए किया है जो आतंकवाद की अपनी परिभाषा के साथ फिट बैठते हैं। एक तरफ चीन शिनजियांग में उइघुर सक्रियता को आतंक का कृत्य बताता है और चाहता है कि दूसरे लोग ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) के विरूद्ध अपनी लड़ाई का समर्थन करें। इसमें दूसरे देशों पर हमला करने वाले कुछ आतंकी समूहों का विरोध करने से भी इनकार किया गया है। उदाहरण के लिए, बीजिंग अपने भू-राजनीतिक हितों का विस्तार करने के लिए पाकिस्तान और उसके आतंक के साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। पेइचिंग ने जैश-ए-मोहम्मद (जैश) के प्रमुख मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर जकी-उर-रहमान लखवी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित करने की भारत की दावेदारी को बार-बार रोक दिया।

कई विश्लेषकों का सुझाव है कि चीनी नागरिकों को अंततः एक बड़ा आतंकी खतरा उजागर हो रही है- और बीजिंग के पास दूसरों से सहयोग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाल की तीन घटनाओं ने निश्चित रूप से चीनी सोच को प्रभावित किया है; क) उइघुर उग्रवादी समूह द्वारा 30 अगस्त, २०१६ को बिश्केक में चीनी दूतावास पर आत्मघाती बम विस्फोट, ख) मार्च 2017 में आईएसआईएस द्वारा जारी वीडियो में स्पष्ट रूप से चीन को अपनी धरती पर हमलों के साथ धमकी दी गई थी। इस्लामिक स्टेट के वीडियो में इराक से लौट रहे जातीय उइघुर को दिखाया गया है और "खून की नदियों" को बहाने की धमकी देने से चीनी चिंता बढ़ गई है, और ग) आंतरिक रूप से, झिंजियांग में स्थिति शैक्षिक शिविरों में नजरबंदी के तहत एक लाख से अधिक उइघुर के साथ तनावपूर्ण है।

इन सबके बावजूद चीन एससीओ समूह के भीतर थोड़ा समन्वय चाहता है। वास्तव में, आतंकवाद के प्रति चीन का दृष्टिकोण अभी भी एक सूक्ष्म बना हुआ है; बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने और एक लक्ष्य बनने से बचने के लिए-कारण है कि चीन उग्रवाद और अलगाववाद के साथ आतंकवाद क्लब जाहिरा तौर पर व्यक्त करने के लिए कि यह इस्लाम के विरूद्ध नहीं है। इससे इस तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता कि शिनजियांग में चीन का दमन बड़े पैमाने पर मुस्लिम विरोधी नीतियों के खतरों को दर्शाता है। अभी तक पश्चिमी देशों ने शिनजियांग में चीन की आतंक विरोधी नीतियों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया है।

जाहिर है, 9/11 के बाद अपनाई गई 'वारन टेरर 'की चीन की मौजूदा अवधारणा आतंकवाद के खतरे को कम करने में नाकाम रही है। चीन में आतंकवादी हमलों से हताहतों की संख्या बढ़ रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिनजियांग इस क्षेत्र में बार-बार सुरक्षा पटाक्षेप के बावजूद 9/11 के बाद चीन में आतंकवाद का केंद्र बिंदु बन गया है। दरअसल, शिनजियांग में उईघुर नृवंश-राष्ट्रवाद से धार्मिक कट्टरपंथ में वैचारिक बदलाव देखने को मिला है। कई विश्लेषकों को संदेह है कि आतंकवाद के प्रति चीन का दृष्टिकोण बदल सकता है क्योंकि अधिक चीनी नागरिक दुनिया भर में अधिक आतंकी जोखिम के संपर्क में आ सकते हैं।

आतंकवाद का मुकाबला

व्यावहारिक रूप से एससीओ ने क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों को पूरा करने के लिए अपने चार्टर होने के बावजूद आतंकवाद से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी है। वास्तव में, मास्को और बीजिंग की चिढ़ के लिए, मध्य एशियाई सदस्यों, विशेष रूप से उजबेकिस्तान, अमेरिकी ठिकानों और सैंय बलों को अपनी धरती पर तैनात होने के लिए आमंत्रित किया।

भारत के लिए, एससीओ से अब तक के लाभों में चमक की कमी साबित हुई है। उदाहरण के लिए, संगठन के आरएटीएस, सैन्य अभ्यासों में भारत की सक्रिय भागीदारी ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश द्वारा प्रायोजित फरवरी 2019 पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले को नहीं रोका है।

एससीओ का ध्यान अफगान संघर्ष को निपटाने और मध्य एशिया और शिनजियांग में आईएसआईएस के प्रवाह को विफल करने के बारे में अधिक रहता है-पाकिस्तान प्रायोजित जेहादियों पर अंकुश नहीं। इसके बजाय सदस्य देश आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान की भूमिका को मान्यता देते हैं। आतंक के विरूद्ध लड़ने में अपने अनुभव के वर्षों के कारण, वे पाकिस्तान को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, नहीं तो पाकिस्तान को समूह में रोपिंग का एक कारण नहीं। पाकिस्तान खुद एससीओ में हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने में अपने विशाल अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक है।

.

अब तक चीन दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति के लिए एससीओ टोगार्नर समर्थन का इस्तेमाल करता रहा है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक २०१६ चीनी रुख के साथ तरफा। एससीओ के तत्वावधान में चीन प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अपनी लाइन को टो करने के लिए समय के साथ-साथ कमजोर मध्य एशियाई राज्यों को मजबूर कर रहा है। चीन को यह भी उम्मीद है कि भारत एससीओ की स्थिति के अनुरूप हो, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो। ऐसा नहीं करने पर निश्चित रूप से भारत की ओर से एक अनिर्माणकारी भूमिका के रूप में डब किया जाएगा।

जबकि अब तक दूसरों को लंबे समय से रेत में अपने सिर छिपाने के लिए चुना है और चीन के दोहरे व्यवहार को चुनौती कभी नहीं, लेकिन बीजिंग अब hares के साथ चला सकते है और आतंक पर शिकारी कुत्ता के साथ शिकार। भारत ने आतंकवाद से निपटने पर बात को दबाने के लिए एससीओ फोरम का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर दिया है। अस्ताना शिखर सम्मेलन में पीएम ने पूरा विश्वास जताया कि एससीओ आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए एक नया धक्का देगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि जब पाकिस्तान जो आतंकवाद का स्रोत है, एससीओ द्वारा संरक्षित रहता है तो भारत को कैसे लाभ हो सकता है।

अधिक से अधिक बार नहीं, ' शंघाई आत्मा ' अब तक आतंक पर चीनी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के लिए खड़ा था। यही वजह है कि एससीओ से अब तक नई दिल्ली का फायदा कम साबित हुआ है। फिर भी, भारत सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने पर बीजिंग का सहयोग प्राप्त करने के लिए मंच का लाभ उठा सकता है।

पाकिस्तान फैक्टर

एससीओ का बड़ा सवाल और डाउन साइड पाकिस्तान फैक्टर है जो ग्रुपिंग में भारत के लक्ष्यों में स्पैनर डालता है। इस्लामाबाद एक "ऐतिहासिक अवसर" और "एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर" के रूप में यूरेशिया शरीर में शामिल होने के लिए पंखों में इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वह यूरेशियन सदस्यों को ग्वादर डीप बंदरगाह बेचने के अलावा अपने प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों यानी अफगानिस्तान और कश्मीर को विनियमित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय एकीकरण एजेंडे के रूप में सीपीईसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एससीओ का इस्तेमाल करेगा। दरअसल, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ने लंबे समय से भारत की संप्रभुता को पार किया था जब उन्होंने 1995 में पाकिस्तान के साथ चतुर्भुज यातायात इन ट्रांजिट एग्रीमेंट (QTTA) पर हस्ताक्षर किए थे, जो गिलगित-बाल्टिस्तान को ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में पारित कर रहा था। ताजिकिस्तान भी हाल ही में QTTA में शामिल हो गया और कजाखस्तान सीपीईसी में रुचि दिखाई। संभावित रूप से सीपीईसी और क्यूटीए अन्य एससीओ राज्यों के साथ भारत के संबंधों पर दबाव डाल सकते हैं।

विडंबना यह है कि रूस और एससीओ के अन्य सदस्य 10 जनवरी, 1965 की ताशकंद घोषणा से सबक लेते हुए एससीओ को भारत-पाक तनाव के क्रमिक रूप से विगलन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक बिंदु बनने पर विचार करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने 2015 में कहा था कि एससीओ विवादित मुद्दों पर समझौते और समाधान खोजने के लिए एक "अतिरिक्त स्थल" बन सकता है। इसी तरह के बयान चीनी नेताओं के आए थे, जिनका मानना था कि ' एससीओ में भारत और पाकिस्तान का प्रवेश ' उनके द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाएगा। इसी तरह की भावनाएं कजाख के पूर्व राष्ट्रपति नजरबायेव ने सीआईसीए की बैठकों में भी व्यक्त की हैं।

एससीओ निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को नरम करने में सहायता करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करता है। सकारात्मक पक्ष पर एससीओ सदस्य देशों की सेनाओं के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यासों में शामिल होने के अवसर सहित विभिन्न स्तरों पर बड़े पैमाने पर राजनयिक और सुरक्षा बातचीत की सुविधा प्रदान करता है जहां वे परिचालन विवरणों पर समन्वय करते हैं और खुफिया जानकारी साझा करते हैं। हालांकि, यह जरूरी है कि चीन-पाक रणनीतिक गठजोड़ को तोड़ दे। फिर भी, संदेह और प्रतिद्वंद्विता की लंबी खींची गई परंपरा के अलावा आतंकवाद का मुकाबला करने पर गहरे मतभेदों को देखते हुए पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का रक्षा और सुरक्षा सहयोग चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। एससीओ की क्षेत्रीय गतिशीलता उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां दोनों देश व्यावहारिकता से निर्देशित होने के लिए तैयार हैं।

इसके बजाय, पाकिस्तान चीन के साथ पहले से ही यूरेशिया में भारत के प्रभाव को कुंद करने के लिए अपनी भारत विरोधी बयानबाजी को आगे बढ़ाना शुरू कर रहा है। उदाहरण के लिए, रूस की अध्यक्षता में एससीओ-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में प्रदर्शन पर फर्जी नक्शा लगाने के लिए पाकिस्तान की हालिया घटना जानबूझकर की गई है। इस घटना के चलते भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक से विरोध में वॉकआउट किया। इससे पहले, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत में फैलेCOVID-19 का हवाला देते हुए नवंबर में एससीओ सरकार के अगले प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करते हुए नई दिल्ली के विरूद्ध अभियान खड़ा किया था।.

भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता

एससीओ प्रारूप में भारत के शामिल होने से निश्चित रूप से न केवल अपनी अफगान नीति बल्कि आतंक से जुड़े सभी मुद्दों पर युद्धाभ्यास के लिए एक नई सीमा खुल गई। 2017 में पीएम मोदी द्वारा एससीओ में भारत की आकांक्षाओं को ठीक-ठाक करने के बाद से लाभ देखा

जाता है ताकि अर्थशास्त्र, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग में लाभ उठाया जा सके, निसंदेह कुछ रेडलाइन पर जोर दिया गया है-"क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, आतंक के विरूद्ध एकजुट हों"। जून 2017 सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र में "संप्रभुता", पारदर्शिता, स्थिरता और जिम्मेदारी का सम्मान करने के सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया।

एससीओ न केवल विश्वास निर्माण के अनुकूल माहौल बनाने के मामले में बल्कि सुरक्षा सहयोग के लिए वास्तविक समय अवसर के संदर्भ में भारत के लिए व्यावहारिक निहितार्थ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, आतंकवाद, आतंकवादी अधिनियम और आतंकवादी संगठनों पर एक एकल समेकित कानूनी ढांचे पर एससीओ के नए अपनाए गए मसौदा कन्वेंशन-"सदस्य देशों को आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उपयोग से संबंधित व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना, आतंकवादी गतिविधियों के लिए सार्वजनिक कॉल या अधिनियमों का औचित्य आतंकवाद, और आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण "पूरी तरह से भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।

एससीओ ने 2007 में लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। बेशक, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत वायुसेना-पाक क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों या अभयारण्यों पर वास्तविक समय के कठिन आंकड़े कितना हासिल कर सकता है।

एससीओ में भारत की उपयोगिता की कुंजी

यह सुनिश्चित करने के लिए, सभी बुलंद लक्ष्यों और क्षेत्रीय अनुरूप के बावजूद, असली सहमति या एससीओ में प्रमुख हितधारकों के बीच तालमेल के लिए संभावना कम बनी हुई है। एससीओ में सालाना कुछ अमूर्त घोषणाएं करने के अलावा स्पष्ट रणनीति का भी अभाव है। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि चुनौती केवल अवधारणाओं और मानदंडों की नहीं बल्कि ' अभ्यास ' की बनी हुई है। अब तक, समूह अभी भी व्यावहारिक सहयोग के बजाय सिद्धांतों और क्षमताओं के बारे में बात कर रहा है। किसी भी स्थिति में विरोधाभासी विचार, खासकर अमेरिका के प्रति भारत का रणनीतिक झुकाव एससीओ के भीतर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को गड़बड़ा देगा।

एक नया पाठ्यक्रम atSCO चार्टिंग में भारत की कोशिश केवल रूस और मध्य एशियाई राज्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है लगता है। भारत का सबसे अच्छा रूस है, जो यूरेशिया के केंद्र के रूप में अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने के लिए एससीओ में एक प्रभावी लंगर है और पूरे बोर्ड में गठबंधन का निर्माण करता है।

वास्तव में, यह रूस था जिसने अपने पिछवाड़े में चीन के प्रभाव को पानी देने के लिए मास्को की चाल के हिस्से के रूप में भारतिन को एससीओ में लाया था। विडंबना यह है कि यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे चीन-रूसी संबंधों को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी में बदलना शुरू हुआ। अब यह स्पष्ट नहीं है कि भारत चीन-रूस संबंधों के इस 'नेवरा' में कहां फिट बैठता है। और मास्को, तेजी से बीजिंग पर निर्भर है, यह कठिन और कठिन लग रहा है जैसे ताजिकिस्तान में सैनिकों की स्टेशनिंग के रूप में चीनी सामरिक युद्धाभ्यास का विरोध।

भारत को दिशा पलटने की जरूरत है और क्षेत्रीय मुद्दों पर रूस और मध्य एशियाई सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल की मांग करते हुए यह संभव है। दरअसल, रूस के साथ विचाराधीन कुछ परियोजनाओं जैसे (भारत-ईईयू एफटीए) और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी (आईएनएसटीसी) को फास्ट ट्रैक पर रखे जाने की जरूरत है।

निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक गतिशीलता लाने की क्षमता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनका अभी तक पता नहीं लगाया गया है। इससे भी

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और रूस को मध्य एशियाई गणराज्यों में विशाल रणनीतिक परिसंपत्तियों का उपयोग करके रक्षा उत्पादन में संयुक्त परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए।

भारत के लिए एक बड़ी अनिवार्यता मध्य एशियाई राज्यों के साथ सीधे सहयोग करना है। इस अवसर पर मध्य एशियाई स्वयं एक नया रास्ता अपना रहे हैं जो यथासमय परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव देखा गया है। नए क्षेत्रीय नेताओं ने नए सपने और दिशाओं के साथ विलय कर दिया है, जो अपने पारंपरिक संबंधों पर आधारित क्षेत्र को ढाल रहे हैं-कम से कम राजनीतिक इच्छाशक्ति का नया रूपक्षेत्रीय समेकन विकसित कर रहा है।

जबकि भारत यूरेशियन एकीकरण पथ में प्रवेश करता है, इसे मध्य एशिया के भीतर बदलती राजनीतिक गतिशीलता में कारक बनाने की जरूरत है। ताशकंद में नेतृत्व के हालिया बदलाव के बाद क्षेत्रीय दृष्टिकोण का स्वरूप अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के पक्ष में बदल रहा है। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के नेतृत्व में उज्बेकिस्तान में नई सरकार इस क्षेत्र के अंदर और बाहर देश के रिश्तों को बढ़ाने के लिए अधिक खुली दिखाई देती है। अगर यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है, तो चीन के लिए अपने बीआरआई विजन को साकार करने की राह में आने वाले मुद्दों के व्यापक सेट को दूर करना हमेशा आसान नहीं होगा। वे सोवियत विरासतों को साझा करते हैं और आम बांड मौजूद हैं। उनके बीच के विवर्तनों को कुछ सीमा पार करने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, उज्बेक-कजाख, उज्बेक-किर्गिज और किर्गिज-ताजिक सीमा तनाव के हालिया मामलों को विवादों में मध्यस्थता करने वाली असाधारण शक्तियों के बिना आंतरिक रूप से प्रबंधित किया जा रहा है।.

क्षेत्रीय एकीकरण अब कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान दोनों के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है। क्षेत्रीय अभिनेताओं के बीच व्यापार बढ़ने के साथ, नियमित रूप से आयोजित क्षेत्रीय 'परामर्शी बैठकों ' में सरकारों के बाहर भी गंभीर प्रतिध्वनि है यानी राजनीतिक, अकादमिक और मीडिया हलकों में।

क्षेत्रीय सुरक्षा में उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर मजबूत नीति अपनाई है और वह अमेरिका की मध्य एशियाई रणनीति से जुड़ा हुआ है जिसे भारत आगे बढ़ा सकता है। आने वाले वर्षों में उनके आंतरिक बांड तेजी से मजबूत आ जाएगा और बाहरी वातावरण से किसी भी प्रभाव से अधिक है। भारत को मध्य एशिया के मौजूदा बदलाव का भी फायदा उठाना चाहिए और एससीओ अपने क्षेत्रीय बांड को मजबूत करने की कुंजी है।

एससीओ और इंडियाचिरेलेशन

एससीओ निश्चित रूप से चीन के साथ बातचीत बनाए रखने के लिए भारत के लिए एक अच्छा स्थल के रूप में कार्य करता है। अब तक मतभेदों के बावजूद नई दिल्ली और बीजिंग ब्रिक्स जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ आ चुके हैं। इससे पहले एससीओ शिखर सम्मेलनों में चीन और भारत एक-दूसरे की मुख्य चिंताओं का सम्मान करने पर सहमत हुए थे। एससीओ ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा गतिरोध पर चर्चा के लिए देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के लिए मॉस्को में एक अच्छा मंच (साइड-लाइंस पर) उपलब्ध कराया है। तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के वर्तमान संदर्भ में एससीओ के भीतर अभिसरण की मांग करने का कोई भी प्रयास कठिन लगता है। जाहिर है, भारत-चीन सहयोग की गतिशीलता उस स्तर तक नहीं पहुंची

है, जहां दोनों देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इस्राइल के बीच हासिल की गई व्यावहारिकता से निर्देशित होने के लिए तैयार हैं।

इस मंच का उपयोग चीन के साथ बेहतर अभिसरण के निर्माण के लिए किया जा सकता है जो अंततः भारतीय सेना को पीएलए के साथ बातचीत करने और एक दूसरे के बारे में गलतफहमी बहाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। बेशक, रूस, भारत और चीन ने आरआईसी और ब्रिक्स सहित कई बहुपक्षीय मंचों पर सफलतापूर्वक एक साथ काम किया है। जाहिर है, एससीओ तीन देशों के बीच बेहतर रणनीतिक अभिसरण को बढ़ाएगा।

इसके अलावा, भारत को यह देखने की जरूरत है कि चीन-पाकिस्तान संरेखण की तीव्रता को कम करने के लिए मंच का उपयोग कैसे किया जा सकता है जो वास्तव में यूरेशिया तक भारत की सीधी पहुंच को कम करता है। फिलहाल एससीओ पूरी तरह से चीन के विजन के साथ गठबंधन कर रहा है। चीनी उम्मीदें होंगी हो सकता है कि एससीओ चीन, भारत और पाकिस्तान को कनेक्टिविटी के मुद्दे पर बात करने और सीपीईसी परियोजना पर भारत की आपत्ति को कम करने के लिए एक नई गति प्रदान करेगा।

एससीओ में भारत की आकांक्षा

वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक अनिश्चितता का मौजूदा संकुचन एससीओ को अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित करने वाला है। वास्तव में, प्रमुख शक्ति प्रतियोगिता के बाद COVID परिदृश्य में सबसे खराब हो सकता है। चीन अपने यूरेशिया विजन को छोड़ने वाला नहीं है, जबकि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को रोकने की मांग कर रहा है। ये एससीओ को अपनी भूमिका, एजेंडा और भविष्य के प्रक्षेपवक्र के संदर्भ में प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं।

अफसोस की बात है कि मध्य एशियाई सदस्यों को टोकोविड-19 महामारी के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवधान का सामना करना पड़ा है। उनके सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, तेल की कीमतों में गिरावट, रूस से प्रेषण में ५० प्रतिशत की गिरावट, प्रवासी विदेशों में फंसे हुए हैं एट अल ने सामाजिक संकट के असंख्य रूपों का निर्माण किया है। नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक चलेगा जो चीन के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करने के लिए बाध्य है और यहां तक कि क्षेत्रीय भूराजनीति को आकार देने के लिए अपने बीआरआई के एक अद्यतन संस्करण के साथ आते हैं।

सैद्धांतिक रूप से, एससीओ की क्षमता बहुत बनी हुई है, कम टकराव होने के लिए अपने चार्टर की भावना में और अपनी आम सहमति आधारित निर्णयों के कारण। भारत के लिए एससीओ का लाभ वैश्विक प्रवृत्ति को विनियमित करने के इच्छुक एक स्वतंत्र महान शक्ति के रूप में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए मंच का उपयोग करना है। हालांकि एससीओ में भारत का भविष्य का प्रक्षेप पथ ज्यादातर इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत-चीन सुरक्षा और आर्थिक गणनाओं पर संबंधों का वजन कैसे करेंगे। बेशक अमेरिका के प्रति भारत का रणनीतिक झुकाव एससीओ के भीतर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को गड़बड़ा देगा।

एससीओ में शामिल होने से काफी हद तक भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में सुधार होगा बशर्ते भारत थोड़ा लो प्रोफाइल बना रहे और पाकिस्तान के खेल में न खेले। यह समूह लंबे समय तक सदस्य देशों के बीच रणनीतिक विश्वास पैदा करने में सहायता कर सकता है। यह हमारे दो पड़ोसियों-चीन और पाकिस्तान के साथ टकराव, संबंधों के बजाय भारत के रचनात्मक के लिए नए आवेगों को उभार सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अगर आलोचना का केंद्र बिंदु बनने से बचने में सफल रहा तो अच्छा करेगा।

भारत निश्चित रूप से अपने इतिहास, भूगोल, संस्कृति और प्रतिस्पर्धी रणनीतिक हितों का संतुलन रखने की अपनी सौम्य छवि के कारण एक संभावित प्रमुख हितधारक हो सकता है। जाहिर है, भारत के लिए रूस और चीन की तुलना में मध्य एशियाई सामरिक स्वायत्तता को मजबूत करने का भी मामला है। भारत का अपना प्रत्यक्ष हित मध्य एशिया को एक बार फिर महान खेल प्रतिद्वंद्विता का भू-राजनीतिक बिसात बनने से रोकने में निहित है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों का लाभ उनके द्वारा उठाया जा सकता है।.

इस क्षेत्र को आतंकवाद और उग्रवाद का केंद्र बनने से रोकने में एक उच्च हिस्सेदारी निहित है-अरब स्प्रिंग प्रकार जैसी राजनीतिक उथल-पुथल वांछनीय नहीं है।

आर्थिक मोर्चे पर, मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार अभी भी सिर्फ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ है, रूस के साथ 10 अरब अमेरिकी डॉलर का और अधिक का हिसाब है। एससीओ सदस्यों (९० प्रतिशत) के साथ भारत का अधिकांश व्यापार चीन के साथ है-और इसे प्राप्त करने में एससीओ आवश्यक नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वैश्विक शासन के नाटकीय कमजोर होने को देखते हुए एससीओ जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच के रूप में कोविड के बाद की अवधि में भारत के लिए एक वैकल्पिक विकास और सहयोग मॉडल पेश कर सकता है जिसे अब अनदेखा किया जा रहा है। भारत निश्चित रूप से यूरेशिया में बाइनरी महान शक्ति की राजनीति के विरूद्ध पीछे धकेल सकता है लेकिन यह हासिल करने के लिए कि भारत को एक मजबूत यूरेशियन रणनीति की जरूरत है। कोविद-19 के विरूद्ध लड़ाई ने भारत को आगे बढ़ने के लिए एक मॉडल प्रदान किया है।

एससीओ राज्यों को दवाओं की आपूर्ति की भारत की कोविड-डिप्लोमेसी सफल रही है। जैसे ही भारत ने COVID-19 के साथ रहने के नए सामान्य में प्रवेश किया, अधिकांश प्रतिक्रियाएं, लगभग दो तिहाई स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें सार्वजनिक क्षेत्र से आ रही हैं। इसके अलावा ज्यादातर हेल्थकेयर गुड्स और ड्रग्स की सप्लाई पब्लिक सेक्टर द्वारा की जाती है। जब तक टीके या वैकल्पिक दवाएं नहीं मिल जाती हैं, तब तक लोगों को गैर-फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेपों (एनपीआई) को जारी रखना होगा और भारत ने महामारी के प्रसार से निपटने में सफलतापूर्वक आवश्यक संशोधन किए हैं। भारत को इस क्षेत्र के साथ COVID-19 के लिए अपने निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया साझा करनी चाहिए। रूस पहले से ही कोविड-19टीके स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए भारत के साथ सहयोग की मांग कर रहा है। यूरेशियन आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ संशोधनों के साथ भारतीय चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

इस महामारी ने भारत के लिए कुछ अन्य सकारात्मक परिणामों को भी प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, भारतीय विमानन उद्योग ने सीओवीड-19 प्रत्यावर्तन उड़ान के दौरान मध्य एशिया में विमानन बाजार की एक विशाल क्षमता की खोज की है-अब तक बेरोज़गार। उद्योग यूरेशियन बाजार में यातायात मार्गों और कार्गो नेटवर्क के पोर्टफोलियो का विकास करने लगता है - यह पीछा करने लायक होगा। हालांकि, राजनीतिक बयानबाजी को छोड़कर तात्कालिक कार्यकाल में सदस्य देश द्विपक्षीय और अन्य बहुपक्षीय व्यस्तताओं के जरिए काम करते रहेंगे। दरअसल, चीन द्विपक्षीय सामग्री को एससीओ के दायरे में शामिल करने के पक्ष में रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए, एससीओ स्वाभाविक रूप से एक नाजुक क्षेत्रीय समूह बने हुए हैं। रूस और चीन के हितों के अलावा मध्य एशियाई राज्यों की स्थिति भी उनके हितों के अनुरूप उतार-चढ़ाव करेगी। एससीओ का प्रभावी सदस्य बनने के लिए भारत को द्विपक्षीय साधनों के जरिए इन देशों के साथ अपना ऐवरेज बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, यह भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति प्रदर्शित करने और अपनी साझेदारियों में विविधता लाने का अवसर भी प्रदान करता है।

वास्तव में, मध्य एशियाई राज्य सहज रूप से भारत से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। ये संवेदनशील होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी होते हैं। वे प्रदर्शन के मामले में भारत की तुलना चीन से करना शुरू कर देंगे। अगर और कुछ नहीं, तो एससीओ में शामिल होने के सीमित तात्कालिक लाभ मध्य एशियाई राज्यों के साथ बेहतर रक्षा सहयोग के लिए मुआवजा से अधिक होंगे। भारत के पास

एससीओ के सभी सदस्य देशों के साथ पहले से ही बहुआयामी द्विपक्षीय स्तर के रक्षा सहयोग संबंध हैं। प्रमुख घटकों में सैन्य, प्रशिक्षण और सहायता, संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य हार्डवेयर की सर्विसिंग और उन्नयन, सैन्य उपकरणों का आयात और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। वास्तव में, व्यक्तिगत सदस्य देशों के साथ मौजूदा द्विपक्षीय स्तर के रक्षा सहयोग ढांचे को निम्नलिखित तरीकों से एससीओ ढांचे के तहत इस सहयोग के विस्तार के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए:

रूस

रक्षा सहयोग भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है, जो वर्तमान में सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-M और MTC) के तहत निर्देशित है। सैन्य-से-सैन्य संबंधों के उन्नयन के लिए भविष्य की हथियार प्रणालियों को विकसित करने से लेकर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप मौजूद है।

कज़ाकस्तान

कजाकिस्तान के साथ सहयोग को भारत-कजाकिस्तान संयुक्त घोषणापत्र ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (24 जनवरी, 2009), रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता (82015 जुलाई) और काउंटर टेररिज्म (पिछले 3 मई, 2017 को आयोजित) पर भारत-कजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के तहत विनियमित किया जाता है।

किरगिज़स्तान

किर्गिस्तान के साथ सहयोग सैन्य-तकनीकी सहयोग (1997) पर समझौता ज्ञापन द्वारा निर्देशित है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए किर्गिज सशस्त्र बलों को निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान करता है, संयुक्त पर्वतीय प्रशिक्षण अभ्यास "खंजर" को नियमित आधार पर आयोजित करता है।.

ताजिकिस्तान

रक्षा सहयोग पर भारत-ताजिकिस्तान जेडब्ल्यूजी (2003), भारत-ताजिकिस्तान "रणनीतिक साझेदारी" (2012) और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत-ताजिकिस्तान जेडब्ल्यूजी (पिछले 14 जून, 2017) हमारे सुरक्षा सहयोग को विनियमित करते हैं। भारत ने ताजिकिस्तान को अपने गिसार मिलिट्री एरोड्रम, अयनिइन 2010 को अपग्रेड करने में सहायता की; भारत में बड़ी संख्या में ताजिक अधिकारियों और कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

उज़्बेकिस्तान

उज्बेकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग पर सैन्य और सैन्य-तकनीकी और जेडब्ल्यूजी में सहयोग पर समझौता 2005 से अस्तित्व में था। जुलाई 2015 में रक्षा और साइबर सुरक्षा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विशेष सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पहुंच गई है।

चीन

रक्षा सहयोग और सैन्य जुड़ाव दिसंबर 1988 में जेडब्ल्यूजी की स्थापना के तुरंत बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद सितंबर 1993 में एलएसी के साथ शांति और शांति बनाए रखने पर समझौता हुआ था। शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक और सहकारी साझेदारी (2005), और सीमा रक्षा सहयोग समझौता (बीडीसीए) 2013 सीबीएम के लिए कवर तंत्र; संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है।

सहयोग के महत्वपूर्ण घटकों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी), रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी), भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), राष्ट्रीय रक्षा में प्रशिक्षण शामिल है। अकादमी (एनडीए), सेना शिक्षा कोर कॉलेज, काउंटर-

इनसर्जर और जंगल वारफेयर स्कूल, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल (HAWS) और संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण केंद्र में; किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान में सैन्य कर्मियों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण और कंप्यूटर लैब्स केंद्रों की स्थापना; कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ संयुक्त सेना पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन। डीआरडीओ का डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज (भाजपाई) माउंटेन एक्जामाइजेशन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए बिश्केक में किर्गिज-इंडिया माउंटेन बायो मेडिकल रिसर्च सेंटर (KIMBMRC) चलाता है।

सहयोग के क्षेत्रों में कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से थर्मल और इलेक्ट्रिकल टारपीडो के लिए कलपुर्जों की खरीद भी शामिल है।

शिक्षा सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश

- भारत को एससीओ में संबंधों में तेजी लाने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को जारी रखना चाहिए। चीन भी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की आड़ में द्विपक्षीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।

- भारतीय सशस्त्र बलों को एससीओ प्रायोजित आतंक विरोधी और सैन्य अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ये सदस्य देशों (भारत और पाकिस्तान सहित) की सेनाओं को परिचालन विवरणों के समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने में एक साथ काम करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये सैन्य कूटनीति का एक अनिवार्य तत्व- मिल-टू-मिल संबंधों को मजबूत करने के अलावा भारतीय सशस्त्र बलों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। भारत को अंतरसंचालनीयता के लिए अंग्रेजी भाषा को शामिल करने के लिए जोर देना होगा।

- चीन संयुक्त उत्पादन के लिए अपने कारखानों को मध्य एशिया में स्थानांतरित करने सहित प्रौद्योगिकी, उपकरण और करार सेवाओं की पेशकश करके एससीओ क्षेत्र में विभिन्न विनिर्माण तंत्र स्थापित करना चाहता है। इसके मुकाबले भारत मध्य एशिया में हथियार और उपकरणों का संयुक्त उत्पादन करने की बेहतर स्थिति में है जैसे उसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक रैमजेट क्रूज मिसाइलों के मामले में रूस के साथ किया है।

- भारत और मध्य एशिया के बीच प्रौद्योगिकियों (रूसी मूल) की समानताओं का दोहन किया जाना चाहिए। जेएससी नेशनल कंपनी काज इंजीनियरिंग (कजाकिस्तान

इंजीनियरिंग) जैसी उत्कृष्ट सुविधाएं - 17 रक्षा उत्पादन इकाइयों का एक समूह संयुक्त उद्यमों में भारतीय फर्मों के लिए भारी संभावनाएं प्रदान करेगा।

- कुछ प्रसिद्ध रक्षा औद्योगिक इकाइयों में ZIKSTO, PZTM, जेनिथ, सेमी इंजीनियरिंग, यूरालस्क, और किरोव-मैश-ज़वोद शामिल हैं जो अभी भी गुणवत्ता वाले हथियारों और मरम्मत उपकरणों का निर्माण करते हैं। इसी तरह किर्गिस्तान में जेएससी दास्तान और जेएससी उलन फर्में नौसैनिक आयुध वाहनों में शामिल हैं और सोवियत मूल की प्रौद्योगिकियों को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन इकाइयों की सबसे अच्छी बात यह है कि वे नए हथियार प्रणालियों के लिए अनुसंधान और डिजाइनिंग केंद्र बनाए रखते हैं। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में टी-72 टैंकों और बीएमपी-2सैट चेमकेंट और कराबाल्टा शहरों की ओवरहालिंग की सुविधाएं हैं।.

भारत को उनके साथ तोपखाने बंदूकें, बख्तरबंद वाहन, मिसाइल, छोटे जहाज, विमानन प्रणाली, नौसैनिक उपकरण आदि हथियारों के उत्पादन के लिए सहयोग करना चाहिए। काफी स्पष्ट रूप से, अंतरिक्ष कार्यक्रम, नौसैनिक जहाज निर्माण और वायुशक्ति निर्माण में कजाकिस्तान के साथ साझेदारी करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए संभावनाएं काफी हैं।

- रूस अभी भी इन देशों में काफी प्रभाव डालता है, विशेष रूप से क्षेत्र की सैन्य अनुसंधान सुविधाओं के संबंध में। इसलिए जब भारत मध्य एशिया में हाई-प्रोफाइल रक्षा परियोजनाएं शुरू करने पर विचार करेगा तो मॉस्को के साथ समन्वय जरूरी होगा।

- भारत को नागरिक संकट प्रबंधन और सैन्य त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता निर्माण के लिए साझेदार देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। भारत एससीओ बैनर तले मानवीय सहायता, आपदा राहत और बचाव अभियान में सैन्य मिशनों के लिए संकट प्रबंधन ढांचा तैयार करने में योगदान दे सकता है।

- संभावित सहयोग का एक अन्य क्षेत्र सीमा प्रबंधन से संबंधित है। भारत मध्य एशियाई सीमा रक्षक बलों के साथ सीमा प्रहरियों-बीएसएफ/आईटीबीपी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने अर्धसैनिक बलों का समृद्ध अनुभव प्रदान कर सकता है।

- रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नियमित उच्च स्तरीय संपर्क को आगे बढ़ाना अनिवार्य है। सैन्य तकनीकी क्षेत्र और मिल-टू-मिल दोनों क्षेत्रों में व्यापक क्षमता का पता लगाने की जरूरत है। मौजूदा सहयोग को अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जैसे:

- रूसी इंटेल टेक एक्सपो, रूसी शस्त्र एक्सपो और कजाकिस्तान डिफेंस एक्सपो (KADEX) में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जहां चीनी उपस्थिति आम तौर पर पतली होती है। इसके विपरीत, भारत को अपनी रक्षा प्रदर्शनियों डेफ एक्सपो और एयरो एक्सपो-इंडिया में एससीओ सदस्यों को भी आमंत्रित करना चाहिए,

- शारीरिक प्रशिक्षण, सैन्य युद्ध कौशल, और सैन्य कार्रवाई की पेशेवर प्रवीणता से संबंधित नियमित सैन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन: भूमि, समुद्र और हवा,

- सक्रिय रूप से भाग लेने और एससीओ सैन्य संगीत समारोह का आयोजन भी। इन त्योहारों को छात्रों सहित प्रमुख हितधारकों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय सैन्य परंपराओं को पेश करने के लिए शैक्षिक और मनोरंजक शो को कवर करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए,

- एससीओ में भारत की भूमिका के प्रति जागरूकता, दृश्यता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भारत को साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करने और मजबूत सहयोग के लिए प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों की पहचान करने के लिए नियमित रणनीतिक और सुरक्षा वार्ता और सम्मेलन करने चाहिए। लद्दाख इंटरनेशनल सेंटर और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए) एससीओ में भारत की भूमिका से संबंधित परियोजनाएं शुरू कर चुके हैं।

- चूंकि भारत में पहले से ही एससीओ के सभी सदस्य देशों में रक्षा अताशे तैनात हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि एससीओ के तहत सामूहिक सुरक्षा ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनके कार्यों को रणनीतिक आयाम से फिर से उन्मुख किया जाए।

- एक संरचित नीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए एससीओ से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए रक्षा मंत्रालय में एक समर्पित डेस्क बनाने की जरूरत है।

- भारत और एससीओ के सदस्य देशों के बीच संभावित सहयोग का एक क्षेत्र सीमा प्रबंधन से संबंधित है, विशेष रूप से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ, जो चीन-शिनजियांग प्रांत के साथ लंबी सीमाओं को साझा करते हैं। चीन का डर दक्षिण कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में पर्याप्त उईघुर आबादी की मौजूदगी है, जिसके अलगाववादी आंदोलनों का शिनजियांग के उइघुर से जुड़ाव है।

- एससीओ रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठकों का लाभ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण (खतरों और चुनौतियों) की समीक्षा करने के साथ-साथ कार्य योजनाओं का समन्वय करने के लिए किया जाना चाहिए,

आतंकवाद विरोधी पर सहयोग

भारत के पास एससीओ के सदस्य देशों के साथ आतंकवाद और कट्टरता की घटना का मुकाबला करने के संबंध में एक अच्छी तरह से तैयार तंत्र और एक साझा दृष्टिकोण है। सभी मध्य एशियाई राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने पर जेडब्ल्यूजी नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। भारत मध्य एशियाई विशेषज्ञों को आतंकवाद और सूचना सुरक्षा से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

आमतौर पर एससीओ के सदस्य देशों के साथ भारत के बहुआयामी संबंध हालांकि सीमित रहे हैं लेकिन प्रमुख घटकों में खुफिया, प्रशिक्षण और सहायता का आदान-प्रदान, सैन्य हार्डवेयर की सर्विसिंग और अपग्रेडिंग, उज्बेकिस्तान से परिवहन विमानों का आयात और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से टारपीडो पार्ट्स शामिल हैं। भारतीय नौसेना कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से थर्मल और इलेक्ट्रिकल टारपीडो के लिए स्पेयर पार्ट्स हासिल कर रही है और पानी के नीचे नौसैनिक आयुध के अनुसंधान और विकास पर कजाकिस्तान के साथ सहयोग की एक अच्छी डिग्री है।

गौरतलब है कि एससीओ ने 30 जुलाई, 2007 को बिश्केक में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। एससीओ के अधिकांश सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा को सूचीबद्ध किया है और इसकी गतिविधियों को उनके क्षेत्रों में होने से रोका जाता है। हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि

पाकिस्तान को आतंकी हाफिज सईद समर्थित आतंकी संगठन ' तहरीक-ए-अजादी जम्मू-कश्मीर ' को 8 जून को ' निषिद्ध संगठनों ' की सूची में जमात-उद-दावा (जेयूडी) के लिए एक मोर्चा लगाना था-एक दिन पहले पाकिस्तान अस्ताना शिखर सम्मेलन में 9 जून, 2017 को एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया था। हालांकि, पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध एक सूची में हालांकि कहा गया है कि स्पेन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के फैसले के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पाकिस्तान के डॉन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इस चिंता को लेकर एफएटीएफ के रडार पर था कि वह संयुक्त राष्ट्र के साथ सूचीबद्ध संस्थाओं के विरूद्ध अंकुश का पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है।

भारत और शंघाई सहयोग संगठन: तीन निबंध

सईद को अब जून 2017 में पाकिस्तानी सदस्यता मामले के माध्यम से आने से महीनों पहले घर में नजरबंद रखा गया है। 1 अगस्त को उसकी नजरबंदी को और दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह इस पृष्ठभूमि के विरूद्ध था, LeT ने 7 अगस्त, 2017 को एक राजनीतिक पार्टीमिली मुस्लिम लीग (एमएमएल) की शुरुआत की। भारत ने आतंकवादी संगठनों और उनके मोर्चों के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए शिखर सम्मेलन में एससीओ सदस्यों को धक्का दिया था। लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि यह सब पाकिस्तान के छल की कार्रवाई के बारे में है। 2016 में सईद को ट्रंप के शपथ ग्रहण के दस दिनों के भीतर ' नजरबंद ' कर दिया गया था। लेकिन यह अधिक उसे किसी भी संभावित अमेरिकी सैंय हड़ताल के विरूद्ध की रक्षा के लिए, से अपनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का इरादा था।

भारत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस क्षेत्र में कोई अवांछनीय तत्व ऐसा आधार न हो जो उसके हित के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आरएटीएस के साथ मिलकर काम करना बेहद महत्वपूर्ण होगा।

इसी तरह, अतीत में भारत के विरोधी कई अवांछनीय और अवांछित तत्व भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मध्य एशिया को सुरक्षित स्वर्ग के रूप में देख रहे हैं। इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में ऐसे तत्वों को अपना स्तर न मिल सके। आरएटीएस के साथ मिलकर काम करना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।

एससीओ ने पहले ही 2007 में लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के तात्कालिक प्रयासों में जैश, मसूद अजहर और एच इज़बुल मुजाहिदीन (एचएम), सैयद सलाउद्दीन को एससीओ द्वारा "वैश्विक आतंकवादी" के रूप में नामित किया जाना शामिल होना चाहिए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 जून, 2017 को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के तुरंत बाद भारत ने 15 जून, 2017 को ताशकंद में एससीओ के आरएटीएस के मुख्यालय में अपना झंडा बुलंद किया है। ताशकंद में आरएटीएस के मुख्यालय में तैनात होने के लिए भाषा कौशल वाले कुछ प्रतिभाशाली अधिकारियों का होना महत्वपूर्ण होगा।

भारत के नजरिए से एससीओ व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ में आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए एक तटस्थ मंच के रूप में इस् तेम कर सकता है। निश्चित रूप से, शंघाई स्पिरिट के माध्यम से लिए जा रहे निर्णयों से भारत उन परिणामों पर बातचीत करने में भी सक्षम होगा जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता हासिल करने में अपने हितों की सेवा करते हैं।

वास्तव में, एससीओ चार्टर का एक प्रमुख सिद्धांत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का संयुक्त रूप से प्रतिकार करना है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने पर बीजिंग का सहयोग प्राप्त करने के लिए मंच का लाभ उठाया जा सकता है या कम से कम चीन आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान का अनावश्यक पक्ष नहीं रखता है।

जाहिर है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन घोषणा में वैश्विक आतंकी समूह आईएसआईएस और अलकायदा के साथ पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-तैयबा को कोष्ठक बनाने के बीजिंग के समर्थन ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। उम्मीद है कि अब से सोच की यह लाइन एससीओ शिखर सम्मेलन में भी दोहराई जाएगी।

अंत में, वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए, अगले एससीओ शिखर सम्मेलन का एजेंडा मौन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, शायद COVID-19 के विरूद्ध लड़ाई पर सहयोग को गहरा करने के लिए दस्तावेजों को अपनाना। इसके बावजूद भारत को इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए यूरेशियन निकाय में अपनी राजनीतिक भूमिका को दोहराने के लिए नवंबर में एससीओ के प्रमुखों की बैठक का इस्तेमाल करना चाहिए।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

Endnotes

1. “Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential,” International Crisis Group – Asia Report No. 33, April 4, 2002.

G. D, Yuan, “China’s Role in Establishing and Building the Shanghai Cooperation Organization (SCO),” Journal of Contemporary China 19no.67: (2010), 855-867.

2. G. D. Yuan, “China’s Role,” 860.

3. “St. Petersburg Summit of SCO Concludes with Rich Fruit,” Xinhua News Agency, June 7, 2002.

4. Stephen Blank, “The Shanghai Cooperation Organization and its Future,” Central Asia & Caucasus Analyst, May 22, 2002.

5. Sherman Garnett, “Challenges of the Sino-Russian Strategic Partnership,” The Washington Quarterly24: No. 4 (2001), 41-54.

6. Robert Cutler, “The Shattering of the Sino-Russian Entente over the Shape of Central Asia?” Central Asia & Caucasus Analyst, November 21, 2001.

7. “Kazakh President Points to Importance of Shanghai Five Summit,” ITAR-TASS News, June 18, 2000.

8. P. Stobdan, “India’s Stakes in SCO”, IDSA, June 15, 2016.

9. RATS SCO, “Director of the Executive Committee of the SCO Rats Speaks about new Challenges and Threats to Security”, 20 June 2016, http://ecrats.org/en/news/6176?sphrase_id=3970

10. RATS SCO, “YevgeniySysoyev: Europeans Believe Sco Rats Is A Successful Platform To Combat Terrorism”, 24 June 2016, http://ecrats.org/en/news/6175?sphrase_id=3970

11. Even Islam Karimov said at the 2015 Ufa summit that the inclusion of India and Pakistan would change the very character of SCO.

http://www.ft.com/cms/s/0/b51a6ae2-2716-11e5-9c4e-a775d2b173ca.html#axzz4BNHJc9tp

12. The Silk Road Economic Belt focuses on bringing together China, Central Asia, Russia and Europe (the Baltic), linking China with the Persian Gulf and the Mediterranean Sea through Central Asia and the Indian Ocean. See, “Chronology of China's Belt and Road Initiative,” Xinhua, March 28, 2015.

13. “SCO paradigm of global, regional cooperation: Chinese FM”, Xinhua, May 25, 2016.

14. The Modi government has indicated the outlines of strategic cooperation with the US in the Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region, agreed in January 2015.

15. Wang Yi endorsed the idea of Iranian membership, but also urged focus on the accession of India and Pakistan. “SCO to consider Iran's accession after India, Pakistan,” Sputnik, May 25, 2016

16. Read the English rendition of Prepared text of Press Statement by Prime Minister at SCO Summit in Astana (June 09, 2017). http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/28518/English_rendition_of_Prepared_text_of_Press_Statement_by_Prime_Minister_at_SCO_Summit_in_Astana_June_09_2017

शंघाई सहयोग संगठन, अफ़ग़ानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा

-पी. स्टोबदान

साल 2001 में अपने आरंभ के साथ हीं शंघाई सहयोग संगठन अफ़ग़ानिस्तान में अस्थिरता को लेकर फ़िक्रमंद रहा है। एससीओ के सदस्य देशों ताज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चीन के साथ अफ़गानिस्तान की सरहदें सटी होने की वजह से इन देशों के लिए आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा अफगानिस्तान से उठने वाली कई छोटी-बड़ी दूसरी चुनौतियां भी चिन्ता का सबब बनी हुई हैं। दरअसल एससीओ का दावा है कि इस संगठन को बनाने के पीछे मुख्य वजह अफगानिस्तान ही रहा है ताकि सदस्य देश सामूहिक रुप से उन फ़ौरी खतरों से निपट सकें जो 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुए अफगान संघर्ष के बाद से इस पूरे क्षेत्र को हलकान करते रहे हैं।[1]

9/11 से पहले भी, रूस और मध्य एशियाई देश हमेशा अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित आतंकवादी समूहों जैसे कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उजबेकिस्तान (आईएमयू), ईटीआईएम, हिजबत-तहरीर (HUT)) और ऐसे ही दूसरे संगठनों से इस क्षेत्र के लिए ख़तरे के बारे में बात करते रहे हैं। इन संगठनों का मक़सद मध्य एशिया में हालात को अस्थिर करना और क्षेत्र में लटपटाती सत्ताओं को मुस्लिम ख़लीफाओं के शासन में तब्दील करना रहा है ।2

वास्तव में जिस वक्त 15 जून 2001 को एससीओ ने आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से निपटने को लेकर पर शंघाई समझौते पर हस्ताक्षर किया या फिर यूं कहें कि साल 2002 में RATS के गठन के वक्त से ही अफगानिस्तान एससीओ की बैठकों में सबसे बड़ा मसला बना रहा। जब राष्ट्रपति हामिद करजई की अगुवाई में अंतरिम अफगान सरकार की स्थापना की गई थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ 2002 की बैठक में औपचारिक तौर पर "आतंक, जंग, ड्रग्स और गरीबी से मुक्त एक नए, स्थिर अफगानिस्तान के निर्माण" का स्वागत किया गया और तमाम अफ़गानियों के हित में व्यापक प्रतिनिधि सरकार बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की पेशकश भी की गई।3

बाद के एससीओ शिखर सम्मेलनों में भी सदस्य देशों ने आतंकवाद, चरमपंथ और नशीले पदार्थों की तस्करी के ख़िलाफ़ जंग और अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया है।4

अफगानिस्तान के स्थिरीकरण में यूएस / नाटो फोर्सेज़ के साथ संलग्न होने के लिए, एससीओ को इस विचार ने ही मौलिक तर्क प्रदान किया।5

एससीओ-अफ़गान संपर्क समूह

साल 2005 आते आते एससीओ सदस्यों ने आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सामूहिक तौर से लड़ने के लिए अफगानिस्तान के साथ सहयोग के मकसद से एक औपचारिक एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थापना करने की ज़रुरत को शिद्दत से महसूस किया। इसके बाद, अफगानिस्तान पर एससीओ की दिलचस्पी लगातार बनी रही। साल 2009 में, एससीओ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी उप सहायक सचिव और यूरोपियन यूनियन, नाटो, ओएससीई, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन(CSTO) और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) आदि के नुमाइंदो की भागीदारी के साथ मास्को में अफगानिस्तान पर एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अहमियत को रेखांकित किया। । 6

एससीओ और अफगानिस्तान ने "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को अपनाने" की भी अपील की। 7

हालांकि दरहक़ीक़त, अफ़ग़ान विवादों से निपटने के लिए एससीओ के प्रयासों की प्रभावशीलता, ख़ास तौर से नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रवाह के संबंध में, निराशाजनक रही है। और 2009 तक, शंघाई सहयोग संगठन-अफ़ग़ानिस्तान संपर्क समूह का वजूद ख़त्म हो गया।

अपनी सेना को वापस लेने के अमेरिकी फ़ैसले के बाद यूरेशिया के लिए अफगान समस्या की प्रकृति में तब्दीली आई है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया (सीरिया और इराक) में दहशत का माहौल पैदा हुआ। खासकर पश्चिम एशिया से यूरेशिया तक आईएसआईएस के खतरे के चलते आशंकाएं गहराती चली गईं। तब से एससीओ शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा को खास तवज्जो दे रहा है। भारत सहित एससीओ सदस्यों के कमोबेश हर नेता ने ये महसूस किया है कि एससीओ अफगानिस्तान को स्थिर करने में अहम किरदार निभा सकता है, खासकर विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद। केवल चीन ही नहीं बल्कि रूस ने भी माना कि अफगानिस्तान के हालात का क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर सीधा असर है।8

वास्तव में साल 2012 में एससीओ के विस्तार पर चर्चा के तार अफगानिस्तान में हिंसा के बढ़ने से ही जुड़े थे। एससीओ के कुछ संयुक्त सैन्याभ्यास अफगानिस्तान से पैदा होने वाले खतरों को दूर करने की रणनीतियों पर ही केंद्रित थे। साल 2012 में एससीओ के बीजिंग शिखर सम्मेलन में, चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने अफगानिस्तान पर्यवेक्षक का दर्जा देने के एससीओ के फैसले का ऐलान किया। 9

बिश्केक में आयोजित तेरहवें SCO शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान से नाटो की वापसी के असर पर ग़ौर किया गया। 10 अक्टूबर, 2013 को किर्गिस्तान ने अफगानिस्तान के हालात पर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें "आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नाजायज मादक पदार्थों की तस्करी और दूसरे अंतरराष्ट्रीय खतरों के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त कार्रवाई" पर जोर दिया गया। 10

वास्तव में, विश्लेषकों का मानना था कि ये अफगानिस्तान है ना कि भारत, पाकिस्तान या फिर ईरान, जो एससीओ की वास्तविक प्रासंगिकता को तय करेगा।

एससीओ का अफ़ग़ान परिपेक्ष्य

हालांकि, ख़ुद ऑब्जर्वर होने के बावजूद अफ़ग़ानिस्तान एससीओ में अपनी भूमिका और अपेक्षाओं को लेकर उदासीन और अनिश्चित रहा। ये संभवतः अफगानिस्तान के अंदरुनी हालात थे जिसने काबुल को अपने उत्तर स्थित पड़ोसियों के विकास को लेकर ज्यादा उत्साही नही बनने दिया। निश्चित रूप से, अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर अमेरिकी नीतियों का भी कसाव था जिसने मंगोलिया की तरह अफगानिस्तान को

भी एससीओ में शामिल होने को लेकर ज्यादा झुकाव नहीं रहा। मुमकिन है कि काबुल को हाई वोल्टेज भू-राजनीति का एक मंच होने के चलते एससीओ से दूर रहना हा गवारा था। हाई वोल्टेज भू-राजनीति को एक व्यंजना के तौर पर लिया जा सकता है जिसमें यूरेशिया पर प्रभाव के लिए अमेरिका-चीन-रूस प्रतियोगिता चल रही थी।

अफगानिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो सिल्क रुट प्रोजेक्ट जैसे नरम मसलों पर सहयोग दूसरी बात थी लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर अफगानिस्तान ने हमेशा इस पक्ष को मजबूती से रखा कि उसके के लिए परेशानी का सबब आंतरिक स्रोतों से कम लेकिन बाहरी स्रोतों से खास तौर से एफएटीए (पाकिस्तान), फरगना (मध्य एशिया), और चेचन्या (रूस) से ज्यादा है। 11

हालांकि क्षेत्रीय सुरक्षा के बदले हुए माहौल में खास तौर से साल 2014 के पश्चिमी सैनिकों की अपील के मद्देनजर, एससीओ को लेकर अफगानिस्तान के नज़रिए में भी तब्दीली आई। एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में उसमें शामिल होने के पक्ष में असरदार अफगान हलकों में भी बहस शुरू हो गई। 12

अफगानिस्तान के नज़रिए से, दो दक्षिण एशियाई देशों, पाकिस्तान और भारत, के बीच की प्रतिद्वंद्विता समस्या का मूल कारण नहीं है लेकिन वो मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राजनीति को रेग्युलेट करने के लिए एससीओ में अपनी स्थिति का लाभ उठाना भी चाहेगा, क्योंकि एससीओ में इस तरह का प्रवेश अफगानिस्तान के लिए एक ऐसा परिणाम है जिसकी चाहत उसे हमेशा रही । लिहाजा अफगानिस्तान ने अपनी समस्याओं के लिए क्षेत्रीय समाधान की तलाश में एससीओ में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान न केवल SCO शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है बल्कि पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। 2018 में, राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने उच्च स्तरीय अफगान प्रतिनिधिमंडल के साथ किंगदाओ में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वहीं अपनी तरफ़ से एससीओ भी अफगानिस्तान की सुरक्षा और माली हालात पर ज़्यादा जोर दे रहा है, खासतौर से उन हालात में जब अफगानिस्तान में आईएसआईएस की मौजूदगी बढ़ी है।

साल 2015 में, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय देशों के सहयोग पर अधिक जोर दिया। जिसके बाद एससीओ के सदस्य देशों और विशेष रूप से रूस ने क्षेत्रीय देशों पर जोर दिया जिन्होंने अफगान सरकार और तालिबान को शांति वार्ता के लिए एक टेबल पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 रूस ने तालिबान के साथ संपर्क भी बनाए।

2016 में ताशकंद में आयोजित सोलहवें एससीओ शिखर सम्मेलन में, सुरक्षा के मसलों के इतर सदस्य देशों ने अफगानिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग पर चर्चा की ताकि अफगानिस्तान को इस क्षेत्र में पारगमन केंद्र के रूप में, खासतौर से बिजली की आपूर्ति और रेल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, विकसित किया जा सके। जाहिर तौर पर

साल 2016 तक, अफगानिस्तान ने एससीओ की योजना में अपनी क्षेत्रीय भौगोलिक निकटता और मध्य एशिया, चीन और दक्षिण एशिया के साथ अपने माली ताल्लुकातों को ध्यान में रखते हुए अधिक योजना बनाई। इसलिए, अफगानिस्तान को उस क्षेत्रीय सुरक्षा परिसर के रुप में ढूंढा जा रहा है जहां साझा क्षेत्रीय समस्याओं का एक सामान्य समाधान मिल सके।

आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के साथ-साथ मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने और आर्थिक विकास में सहयोग के लिए एससीओ एससीओ के मध्य एशिया के सदस्य देश अफगान मसले को क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय जटिलता के सबसेट के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए, एससीओ के लिए अफगान समस्या एक महत्वपूर्ण चिंता बन गई और अफगानिस्तान के संगठन के पूर्ण सदस्य बनने आवश्यकता भी महसूस होने लगी। ये एससीओ के लिए अपने क्षेत्रीय एजेंडे को पूरा करने के लिए ज़रुरी था। कई विश्लेषकों ने ऐतिहासिक, जातीय, और अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक समानता को साझा करना शुरू कर दिया था। जाहिर है रूस और चीन भी अफ़ग़ान समस्या का हल एससीओ के ज़रिए ही निकालना पसंद करते हैं।

एक ओर जहां रुस, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ तालिबान सहित अलग अलग मसले हैं वहीं चीन की दिलचस्पी अफ़गान मामलों में इसलिए है ताकि वो अपने बीआरआई और आर्थिक योजनाओं को मज़बूती दे सके। अब चीनी रेलवे उज्बेक रेल लाइन के ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान के मजार-ए-शरीफ से जुड़ चुका है।

संपर्क समूहों का पुनरुत्थान

2017 में संगठन के विस्तार के बाद, एससीओ को अपने एजेंडे और गतिविधियों में जरूरी फेरबदल करना पड़ा। एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह को नौ वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्जीवित किया गया। सीरिया में आईएसआईएस के ख़िलाफ़ अपने अभियान के बीच रूस की अफगान नीति में बदलाव के बाद यह पुनरुद्धार हुआ। मास्को ने मध्य एशिया और दक्षिणी रूस के लिए गंभीर ख़तरा पैदा करने वाले

तालिबान के बजाय अफगानिस्तान में आईएसआईएस की बढ़ती मौजूदगी देखी।इसी के मद्देनजर साल 2017 में राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान से पैदा हो रहे ख़तरों से साझा तौर पर निपटने के लिए एससीओ के विशेष बलों के बीच समन्वय पर जोर दिया। इसी वजह से शंघाई सहयोग संगठन-अफगानिस्तान संपर्क समूह को पुनर्जीवित करने की ज़रुरत महसूस की गई। लेकिन, मास्को ने तालिबान के साथ सुलह प्रक्रिया में शामिल होने के पक्ष में भी विचार किया क्योंकि रूस और चीन दोनों क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। इसी तरह, 2017 में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी "अफगानिस्तान की शांति और सुलह प्रक्रिया में बड़ी भूमिका" निभा रहे एससीओ की सराहना की। यह निश्चित रूप से, अफगानिस्तान के आसपास से गुजरने वाली चीन की BRI और CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, चीन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को मिलाकर एक उप-क्षेत्रीय सुरक्षा समूह बनाकर अपने खुद के दांव लगाने शुरू कर दिये। इसने अफगान तालिबान को सुलह प्रक्रिया में शामिल करने के लिए चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के आपसी संवाद का सिलसिला भी शुरू करवाया. अफगानिस्तान ने बीआरआई पर पूरे सहयोग का भी वादा किया है। राष्ट्रपति गनी को चीन के साथ अफगानिस्तान की दोस्ती रास आती रही है.

इन्हीं परिस्थितियों में संपर्क समूह की पहली बैठक 11 अक्टूबर 2017 को मास्को में उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर आयोजित की गई थी। समूह ने राजनीतिक परामर्श और बातचीत के जरिये संघर्ष को निपटाने के लिए अफगान सरकार का समर्थन किया। रोटेशन के आधार पर इस परामर्शदात्री निकाय के ढांचे के भीतर एससीओ-अफगानिस्तान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। संपर्क समूह की दूसरी बैठक 28 मई 2018 को बीजिंग में और तीसरी 2019 में बिश्केक में आयोजित की गई। एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह ने अफगान शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी लेनी शुरू की , जिसके फलस्वरूप साल 2019 में शांति वार्ता में तेजी आई।14

बिश्केक में आयोजित तीसरी बैठक में संपर्क समूह के आगे की कार्रवाइयों के मसौदे पर चर्चा हुई. 15 गौरतलब है कि एससीओ सचिवालय ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह की भूमिका और उपलब्धियों की समीक्षा के लिए 9 जनवरी 2019 को अफगानिस्तान पर एक गोलमेज चर्चा की। संपर्क समूह अफगानिस्तान में हालात पर नजर रखने के साथ ही अंतर अफगान वार्ता की संभावनाओं का आकलन भी कर रहा है। 16एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने संपर्क समूह के दृष्टिकोण और एजेंडा को विस्तृत किया जिसमें शामिल थे:

• अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर, एससीओ ने पाया कि साल 2019 में स्थानीय आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी हमलों की वारदातों में इज़ाफ़ा हुआ है। विशेष चिंता का विषय मध्य और दक्षिण एशियाई नागरिकों के साथ अफगान सीमा क्षेत्रों में सशस्त्र विपक्ष और समूहों की बढ़ती संख्या थी। एससीओ खासतौर से उत्तरी अफगानिस्तान में कई प्रांतों में केंद्रित कट्टरपंथी ताक़तों को लेकर फिक्रमंद हो चला जहां से चरमपंथी 1990 के दशक की तरह ही मध्य एशिया के देशों में घुस सकते थे।

• एससीओ के मुताबिक अफगानिस्तान में मादक पदार्थों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आतंकियों के राजस्व स्रोत का 65 प्रतिशत से अधिक दवाओं से उत्पन्न होता है। एससीओ का मानना है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में आरएटीएस की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है।

• अफगानिस्तान में यूएस- तालीबान बातचीत, इंट्रा-अफगान वार्ता और अमेरिकी सैनिकों की वापसी जैसे बदलावों के मद्देनजर एससीओ अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने एवं शांति बहाली के लिए अफगान सरकार और लोगों के प्रयास को पूरा समर्थन देने के लिए कृतसंकल्प है।

• अफगान शांति प्रक्रिया के मसले पर एससीओ सदस्य राज्यों द्वारा सुझाये गए विभिन्न संवाद स्वरूपों का समर्थन करता है, जिसमें परामर्श के मास्को प्रारूप, ताशकंद प्रक्रिया, रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों और अन्य बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के साथ परामर्श शामिल हैं।

• एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह ने 2018 में एक रोडमैप को मंजूरी दी, जिसमें सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यों की परिकल्पना की गई थी।

• एससीओ-संपर्क समूह के विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान के हालात सारे एससीओ देशों पर और खास तौर पर मध्य एशियाई राज्यों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और अफगानिस्तान मसले को सुलझाने के लिए चल रहे अमेरिकी प्रयास न सिर्फ महंगे हैं बल्कि नाकाफी भी हैं. उनका मानना है कि राजनीतिक हालात बदतर हुए हैं और अफगान समाज पहले से ज्यादा कट्टरपंथी बन गया है.

• मोटे तौर पर एससीओ का मानना है कि अफगान समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है और एससीओ राज्यों को अफगान लोगों की भागीदारी के साथ आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने में अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए।

• एससीओ का स्पष्ट मानना है कि अफगानिस्तान को खतरों की जमीन नहीं बल्कि अवसरों की भूमि के रूप में देखे जाने की जरूरत है. 'ग्रेटर यूरेशियन' साझेदारी, बीआरआई और सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय रणनीतियों के अनुरूप वायु, सतह और रेलवे कनेक्टिविटी लाइन के क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में देश की भागीदारी को बहाल करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, मौजूदा हेयरटैन - मजारे-शरीफ रेलवे और प्रस्तावित मजारे-शरीफ - हेरात और मजार-ए-शरीफ-पेशावर लिंक को नए ट्रांस-क्षेत्रीय गलियारों के रूप में

देखा जा रहा है ताकि यूरेशियन देशों को भारत, ईरान और पाकिस्तान के बंदरगाहों तक सीधी पहुंच प्रदान की जा सके।

• अनिवार्य रूप से, एससीओ अपने सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम में अफगानिस्तान की सहायता के लिए एक नीतिगत दृष्टिकोण ले रहा है, जिससे कृषि उत्पादन में भागीदारी का अवसर पैदा करना, अफगान युवाओं को एक सकारात्मक एजेंडे में शामिल करना और व्यापक यूरेशियन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अफगान औद्योगिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एकीकृत करना शामिल हैं।

शंघाई सहयोग संगठन, भारत और अफ़ग़ानिस्तान

भारत एससीओ के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। दरअसल अफ़ग़ानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाने के लिए उसके पास जायज वजहें हैं। इसी चलते भारत साल 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के बाद एससीओ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद भारत ने फौरन एससीओ-संपर्क समूह की बैठक में हिस्सा लिया जिसे नौ साल के अंतराल के बाद अक्टूबर 2017 में पुनर्जीवित किया गया। इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर अपना नज़रिया साझा किया और अफगानिस्तान में समृद्धि लाने के प्रयासों में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की।

नई दिल्ली का नजरिया अपनी स्थिति और अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर काफी साफ़ है। भारत ने निरंतर उन आतंकवादी समूहों को नकारा है या उनका विरोध किया है जो जायज़ तरीक़े से बनी अफ़ग़ान सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। भारत का नज़रिया ये रहा है कि कोई भी समझौता अफ़ग़ान के नेतृत्व वाले और अफगान के स्वामित्व वाली शांति और सुलह के प्रारूप में ही होना चाहिए। इस बात भी की भी पूरी संभावना है कि अफगानिस्तान को लेकर एससीओ में भारत का रुख़ दूसरे देशों से अलहदा हों, खासतौर से चीन और पाकिस्तान से। भारत अपनी स्पष्ट और सुसंगत नीति से खुद को अलग नहीं कर सकता है कि वो अच्छे और बुरे तालिबान के बीच फ़र्क़ नहीं करता है।

भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने के हक़ में नहीं है। लेकिन वो आतंकवाद से पैदा होने वाली चुनौतियों का मुक़ाबला करने के लिए एससीओ की कोशिशों की हिमायत करता है और इस विचार का समर्थन भी कि अफ़गान सैन्य बलों को मज़बूत किया जाना ज़रुरी है।17

इसके लिए भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ काम कर रहा है। तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच एक राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिशों में भी भारत शिद्दत से जुटा हुआ है। भारतीय अधिकारी साझा मक़सदों को हासिल करने के लिए शांति पहल को और मज़बूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं।

दशकों से भारत का अफगानिस्तान के प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण रहा है। भारत, अफगानिस्तान के नागरिक पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काबुल का समर्थन करने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध है। भारत अफगानिस्तान की जनता की प्राथमिकताओं के आधार पर सामाजिक-

आर्थिक विकास के लिए मदद देना जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अधिक कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण सुनिश्चित करेगा। भारत, रूस और चीन के लिए यह मुमकिन हो सकता है कि वे अफगानिस्तान में सहयोगात्मक तरीके से काम करने की अनिवार्यता खोजें - श्रम को साझा करने की भावना से। SCO में अफगानिस्तान की सदस्यता के लिए भारत ने अपना जोरदार समर्थन दिया। लेकिन एससीओ की अगुवाई में अफगान के अमन को लेकर क्षेत्रीय सहमति बनाने में भारत किस हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ये एक अहम मसला है। अन्य मध्य एशियाई सदस्यों और रूस के लिए, उनके पास अफगानिस्तान-मध्य एशियाई सीमाओं के साथ खतरों का मुकाबला करने के लिए सीएसटीओ के तहत पर्याप्त तंत्र हैं।

भारत इस मसले पर अफगानिस्तान के नेतृत्व वाले और अफगान के स्वामित्व वाली शांति और सुलह के प्रारूप के अनुसार चलने को विवश है। भारत का मानना है कि आईएसआईएस को सैन्य कार्रवाई के जरिये ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन तालिबान को राजनीतिक रूप से वैध बनाने के किसी भी प्रयास से पूरे दक्षिण और मध्य एशिया के प्रभावित होने का खतरा है. इसके अलावा, भारत का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य स्रोत है और सभी आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंध हैं। और, अगर तालिबान सत्ता में आता है, तो इस्लामाबाद इस क्षेत्र में भारतीय हितों को आघात पहुंचाने के लिए एससीओ में कई भारत- विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देगा.

इसलिए मौजूदा हालात में तालिबान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर उत्तरी-गठबंधन की तरह का काउंटर समूह बनाने की कोई भी योजना शायद ही सफल हो।

भारत के नजरिये से, अफगानिस्तान का एससीओ के करीब आना तो एक सकारात्मक बात होगी लेकिन मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच पुल बन रहा अफगानिस्तान तब तक एक नारा बनकर रहेगा जब तक पाकिस्तान रचनात्मक भूमिका नहीं निभाता। यह संभव है कि भारत और चीन के लिए अंततः अफगानिस्तान में सहयोगात्मक तरीके से एक साथ काम करने की अनिवार्यता हो जाए।

भारत के लिए चुनौती यह है कि अपने रणनीतिक एजेंडे पर कायम रहते हुए अफगानिस्तान में नये आर्थिक अवसरों का लाभ कैसे लिया जाए. ये अवसर विनिर्माण, परिवहन और निर्माण के क्षेत्र में हो सकते हैं। मध्य एशिया के सूखा मेवा उत्पादन केंद्रों को अफगानिस्तान के साथ जोड़कर भारत और दुनिया भर में आपूर्ति के लिए ड्राई-फ्रूट सप्लाई चेन बनाने के लिए एक पहल कर सकता है। इसके अलावा भारत को अफगानिस्तान के कृषि और सिंचाई क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में भी आगे बढ़ना चाहिए।

एससीओ-संपर्क समूह के भीतर अफगान मुद्दे पर अलग-थलग नहीं होने के लिए, भारत को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान (KUT) और रूस के साथ बेहतर समझ स्थापित करनी चाहिए। के यू टी , एस सी आे के भीतर भारत के लिए अधिक विश्वसनीय भागीदार बना सकता है।

भारत को आर ए टी एस के भीतर के यू टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अफगानिस्तान सहित सदस्य राज्यों के बीच ऐसे तंत्र को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे निम्नलिखित कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके

(क) द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते, (ख)एफटीए/वजीरिस्तान समेत पूरे क्षेत्र में सक्रिय कट्टरपंथी चरमपंथियों और आतंकवादियों का जायजा लेना (ग) उनकी गतिविधियों पर गहरी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना (घ) आतंक-वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान करना और संयुक्त रूप से इन चैनलों को अवरुद्ध करने की दिशा में काम करना और (च) संयुक्त रूप से मौलाना और सुफी धर्मगुरुओं की मदद से भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना.

सहयोगियों के बारे में

राजदूत (सेवानिवृत्त) योगेन्द्र कुमार

राजदूत योगेंद्र कुमार साल 2012 में भारतीय विदेश सेवा से भारत सरकार के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। अपनी सेवानिवृत्ति के समय, वे पलाऊ, माइक्रोनेशिया और मार्शल द्वीप के प्रशांत द्वीप देशों की समवर्ती आधिकारिक मान्यता के साथ फिलीपींस में भारतीय राजदूत थे। इससे पहले वो नामीबिया में उच्चायुक्त और ताजिकिस्तान में राजदूत (2000-03) रहे हैं, जिसके दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से जुड़े मामलों को भी संभाला। उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज के संकाय में भी सेवा की है और विदेश मंत्रालय में उन्होंने जी8-जी5 वार्ता, आसियान, ईएएस, आईबीएसए, आईओआरए आदि जैसे बहुपक्षीय संगठनों / संवादों को भी संभाला। सेवानिवृत्त होने के बाद से, वे विदेश नीति व सुरक्षा से जुड़े मामलों पर लिखते और बात करते रहे हैं।

उनकी पुस्तक, 'डिप्लोमैटिक डाइमेंशन ऑफ मैरीटाइम चैलेंज्स फॉर इंडिया इन द 21 सेंचुरी', साल 2015 में पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है। उन्होंने हिंद महासागर नीति पर प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक भाषण पर नवंबर, 2016 में आयोजित एक सेमिनार में प्रसिद्ध सुरक्षा एवं विदेशी सेवा विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों / लेखों वाली पुस्तक 'विदर इंडियन ओशन मैरीटाइम आर्डर' को संपादित किया और इसमें अपना योगदान दिया। 2017 में नॉलेज वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित, इस पुस्तक को भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मार्च, 2017 में जकार्ता में पहले हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ लीडर्स समिट में अपने-अपने राज्य / सरकारों का नेतृत्व करने आए प्रतिनिधिमंडल को प्रस्तुत किया।

उनसे mr_yogendra_kumar@hotmail.com के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

सहयोगियों के बारे में

राजदूत पी. स्टोबदान

राजदूत पी. स्टोबदान एक प्रसिद्ध रणनीतिक संबंध विशेषज्ञ एवं एससीओ से संबंधित मुद्दों पर भारत के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं। उन्होंने अल्माटी (कजाकिस्तान) में स्थित भारतीय दूतावास में निदेशक / पहले सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में संयुक्त निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इसके पश्चात, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल स्टडीज के निदेशक / प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। 2012 तक, उन्होंने किर्गिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया।

राजदूत स्टोबदान वर्तमान में लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, लेह के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा, वो एक प्रमुख स्तंभकार भी हैं।

वह वाशिंगटन डीसी में स्थित मध्य एशियाई मामलों की ऑक्सस सोसाइटी की सलाहकार परिषद में भी शामिल हैं। उनकी हालिया पुस्तक में शामिल हैं: *'द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालय: इंडिया एंड चाइनाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस'* साल 2019 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्रकाशित की जा रही है। *'इंडिया एंड सेंट्रल एशिया: द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन'* केडब्ल्यू पब्लिशर्स, नई दिल्ली 2020 द्वारा प्रकाशित होगी।

भारत और शंघाई सहयोग संगठन: तीन निबंध

1. भारत और शंघाई सहयोग संगठन - योगेंद्र कुमार
2. भारत के संदर्भ में शंघाई सहयोग संगठन के उद्देश्य एवं प्रासंगिकता: आकलन - पी. स्टोबदान
3. एससीओ, अफगानिस्तान एवं क्षेत्रीय सुरक्षा - पी. स्टोबदान

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजु के नेतृत्व में प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारत का दृष्टिकोण तैयार करना और विदेश नीति के मुद्दों पर सूचना व विचार के केन्द्र के रूप में कार्य करना था। वर्तमान में यह परिषद अपने यहां मौजूद संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीतिगत शोध करती है। यह परिषद नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करती है और कई प्रकाशन भी जारी करती है। परिषद के पास एक अच्छी तरह से सज्जित लाइब्रेरी, सक्रिय वेबसाइट भी है, और यह 'इंडिया क्वार्टरली' नामक पत्रिका भी प्रकाशित करती है। आईसीडब्ल्यूए का अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग को विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन हैं। परिषद की भारत के प्रमुख शोध संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी भागीदारी है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली